VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

सिविल सोसाइटी विश्लेषण

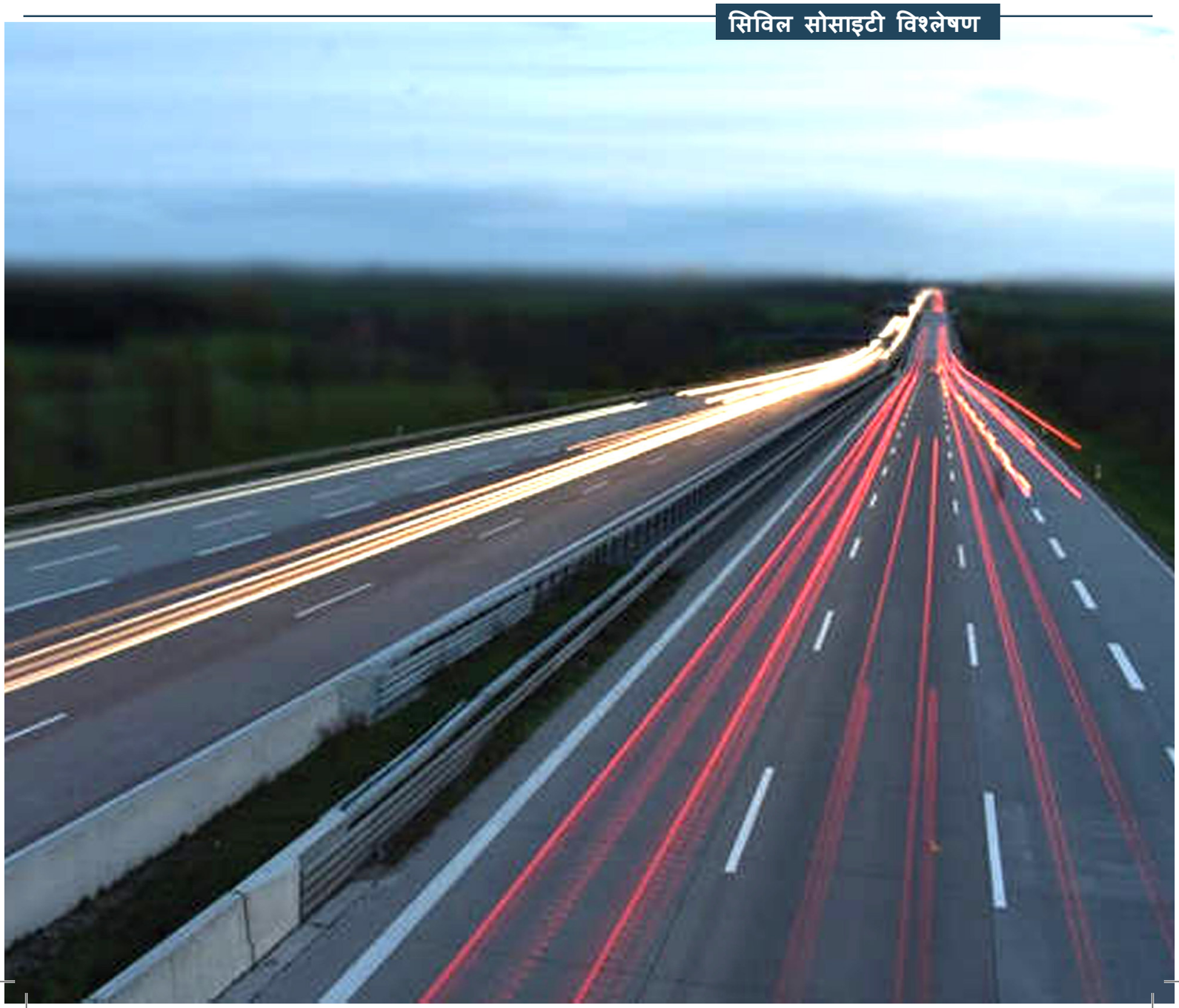

ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

प्रस्तावना

ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका इसके बढ़ते आर्थिक कद और एशियाई भू-राजनीति में प्रदर्शित सक्रियता के कारण लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल साउथ सहयोग के अग्रणी और चैंपियन के रूप में यह सैद्धांतिक रुख के साथ मजबूती से खड़ा है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, 1990 के नवउदारवाद और 2009 के भू-राजनीति के बाद से गरिमा, संप्रभुता और मूल्य-आधारित साझेदारी को बहुत महत्व देता है। इसके अलावा, भारत के बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एमओयू (समझौता ज्ञापन) और विज्ञप्तियो ने हमेशा परियोजनाओं, वित्तपोषण और सहयोग में विकास-उन्मुख विकास पैटर्न की आवश्यकता को रेखांकित किया है। महत्वपूर्ण रूप से, भारत सरकार अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नीति-विकासकर्ता की भूमिका निभाने के लिए सिविल सोसाइटी का स्वागत करती रही है, जिसने विभिन्न विकास सहयोग प्लेटफार्मों और मंचों के निर्माण में मदद की है। इसने अधिक खुलेपन और पारदर्शिता एवं साझेदारी की इच्छा के साथ नीति परिवर्तन के संकेत दिए है। अभी भी कुछ अंतर है जिन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है यदि सिविल सोसाइटी संगठनों को सहयोग पैटर्न में सुधार के लिए नीतिगत इनपुट और सुझाव प्रदान करने के लिए एक निश्चित स्थान दिया जाता है। भारत का विकास सहयोग तीन चरणों- एलओसी, सहायता अनुदान और आईटीईसी पर बना है। हालांकि कई परियोजनाएं द्विपक्षीय एमओयू (समझौता ज्ञापन) है। इसके वाणिज्य, सुरक्षा और कूटनीतिक उद्देश्यों के रूप में कई बड़ी संरचना परियोजनाएं विकसित की जा रही है। ये परियोजनाएं बड़े पैमाने पर विकसित की जा रही है जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को आगे ले जाने के लिए सुनिश्चित करेंगे, जहां वे आधारित है। दुनिया भर में साक्ष्य उपलब्ध है जो यह प्रमाणित करते है कि बड़े पैमाने पर संरचनाएं किसी क्षेत्र की भूमि, पानी, हवा की हानि से सीधा सम्बंधित है। इस नोट द्वारा, सिविल सोसाइटी संगठनों के रूप में, हम चाहते है कि हमारी सरकार ऐसे संरचना निर्माण करे, जो पर्यावरण के अनुकूल, परिस्थिति अनुसार संवेदनशील और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। विचार यह है कि हमारे सिस्टम के भीतर ऐसी विधियों और प्रक्रियाओं को निर्मित करना जिससे परियोजनाओं की सकारात्मकता लोगों और ग्रह को अधिकतम सहायता प्रदान करे। हम अपनी सरकार को विभिन्न विकास सहयोग में भागीदार बनने का सुझाव दे रहे है जो प्रभावी रूप से सामाजिक परियोजनाओं को बढ़ावा देगा। यह न केवल संरचना निर्माण की गुणवत्ता में सहायता करेगा बल्कि हमारे विकास सहयोग उद्देश्यों को विकसित करने और परिपक्व करने में सहायता करेगा। महत्वपूर्ण रूप से, वे विकास सहयोग जो भारत के सिद्धांतों का एक मानक स्थापित करेंगे और अन्य देशों के लिए अनुकरणीय होंगे। इसलिए, यह अध्ययन सरकार को एक रचनात्मक सुझाव प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, न कि एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए। इस रिपोर्ट को लिखने के लिए, मैं अर्जुन फिलिप्स, प्रोग्राम मैनेजर और एचबीएस को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हम आशा करते है कि इस रिपोर्ट द्वारा सरकार को सक्रिय रूप से सुझाव मिलेंगे और विभिन्न विकास पहलुओं पर काम कर रहे स्थापित सिविल सोसाइटी प्लेटफार्मों में उनकी बातचीत के माध्यम से भारत की विकास सहयोग परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे।

धन्यवाद,

हर्ष जेटली

विषय वस्तु

प्रस्तावना	2
अध्ययन का उद्देश्य	4
संरचना को परिभाषित करना	4
शोध का उद्देश्य	4
कार्यप्रणाली	4
विकास सहयोग में भारत की संरचना परियोजनाओं का अवलोकन	5
-भारत का विकास सहयोग	5
-भारत के विकास सहयोग में संरचना विकास	8
संरचना परियोजनाओं के आकलन के लिए संकेतक	9
बांग्लादेश-भारत रामपाल पावर स्टेशन	13
भूटान-भारत जलविद्युत परियोजनाएं	15
म्यांमार-भारत कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट	19
रवांडा-भारत न्याबोरोंगो पावर प्लांट	22
नेपाल-भारत कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन	24
ग्लोबल साउथ में भारत के सहयोग से अन्य संरचना परियोजनाएं	26
सुझाव और निष्कर्ष	28
संदर्भ सूची	29

ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों में लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी), ग्रांट-इन-एड्स और द्विपक्षीय एमओयू के तहत भारत सरकार की विभिन्न संरचना परियोजनाओं के सहयोग का सिविल सोसाइटी विश्लेषण करना है। इस रिपोर्ट में कुल 5 केस स्टडी (अध्ययन रिपोर्ट) का प्रयोग किया गया है।

संरचना को परिभाषित करना

इस शोध का मुख्य उद्देश्य संरचना की जांच करना है जिसमें चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा, उपाय प्रस्तावित किये जायेंगे और निष्कर्ष निकाले जायेंगे । ऊपर उल्लिखित संरचना में सामाजिक जीवन स्थितियों को सक्षम बनाए रखने, और आसपास के वातावरण को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक भौतिक सार्वजनिक उद्देश्य शामिल है । यह अध्ययन मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना चक्र की जांच और समीक्षा करेगा जिसमें सड़कें, राजमार्ग, बांध और इन देशों में भारत द्वारा विकसित हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति तंत्र, सौर संयंत्र, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ शामिल है।

शोध का उद्देश्य

लगभग सभी संरचना निर्माण के परिणामस्वरूप जनसंख्या विस्थापन, भौगोलिक परिवर्तन, स्थानीय आजीविका प्रभावित हुई है और जलवायु की स्थिति बदल गई है। सिविल सोसाइटी संगठनों और पर्यावरणविदों द्वारा नकारात्मक परिवर्तन के लिए चिंता बढ़ती जा रही है जो कि मूल नीति कार्यों के माध्यम से अप्रभावी उपायों और सुरक्षा उपायों के कारण विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ठ संरचना विकास से जुड़े है। कई संरचना परियोजनाएं, परियोजनाओं के मूल्यांकन, प्रारंभिक मूल्यांकन और ईआईए प्रक्रियाओं के लिए प्रोटोकॉल स्थापित करते समय उनका सख्ती से पालन करने में विफल रहती है। दूसरा, सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा परियोजना के विकास चरण में शिकायतों और चिंताओं को निर्विष्ट करने में प्रभाव मूल्यांकन और सहयोग की अनुपस्थिति तथा परियोजना के दौरान और उनके पूर्ण होने पर सिविल सोसाइटी की सहभागिता यह बताती है कि संरचना विकास के प्राथमिक उद्देश्य, यानि विस्तृत आर्थिक लाभ, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा और बिजली जैसी सेवाओं तक पहुंच का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के संरचना विकास सहयोग के उद्देश्य व्यर्थ और अपूर्ण न रहें, जिसके परिणामस्वरूप कल्याण से अधिक नुकसान होता है, यह अनुसंधान चुनौतियों को मजबूत करने का प्रयास करता है और सामाजिक-विकास मूल्यांकन करता है जो निर्धारित परियोजनाओं का मूल्यांकन प्रदान करता है। अनुसंधान के महत्व को बढ़ाने के लिए, पहले से स्थापित विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वे परियोजनाएं जो निर्माणाधीन चरण में है और जिनके एमओयू द्विपक्षीय रूप से लागू किये जा चुके है लेकिन वे अभी तक शुरू नहीं हुई है।

कार्यविधि

यह शोध परियोजना देशों के सहायक साहित्य समीक्षा का अनुसरण करता है जैसे मीडिया रिपोर्ट, शोध पत्र इत्यादि। यह शोध साहित्य अन्वेषण के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र, ओईसीडी, क्यूआईआई पैरामीटर, साउथ-साउथ सहयोग सिद्धांतों और अन्य एजेंसियों के मौजूदा संकेतकों का उपयोग करता है। यह एक संक्षिप्त सूक्ष्म संचालन करना चाहता है। यह परियोजनाओं का मध्यम और विस्तृत विश्लेषण करता है जो परियोजनाओं के प्रत्यक्ष प्रभावों को समझने में सहायक होगा।

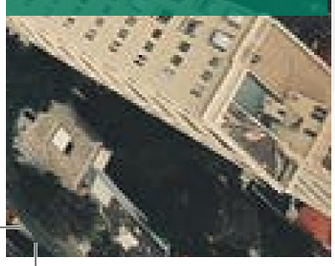

विकास सहयोग में भारत की संरचना परियोजनाओं का अवलोकन

भारत का विकास सहयोग

भारत का विकास सहयोग इसके मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है जो सम्मान, विविधता, भविष्य की चिंताओं और दीर्घकालीन विकास पर आधारित है। भारत के लिए सहयोग का प्रमुख सिद्धांत विकास का सम्मान करना, उनकी विकास प्राथमिकताओं को पूरा करना और आपूर्ति अंतर को ख़त्म करना है।[1] भारतीय विकासात्मक सहयोग का मॉडल व्यापक है और इसमें सहायता अनुदान, लाइन ऑफ़ क्रेडिट और क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता सहित कई उपकरण शामिल है। भागीदार देशों की प्राथमिकताओं के आधार पर, भारत के विकास सहयोग में वाणिज्य से लेकर संस्कृति तक, ऊर्जा से लेकर इंजीनियरिंग तक, स्वास्थ्य से लेकर आवास तक, आईटी से लेकर संरचना तक, खेल से लेकर विज्ञान तक, आपदा राहत और सांस्कृतिक और विरासत संपत्तियों की पुनः स्थापना और संरक्षण के लिए मानवीय सहायता शामिल है।[2] भारत का विविधीकरण इसके विकास सहयोग को निम्नलिखित रूप में प्रदान किया गया है:

भारत का कुल रियायती विकास वित्त 2015 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2014 में यह 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (भारत सरकार, 2015A, 2015B पर आधारित ओईसीडी द्वारा अनुमानित)। भारत ने 2014 में 141 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2015 में बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से 106 मिलियन अमरीकी डालर (इसके रियायती विकास वित्त का 6%) का प्रवाह किया। विदेश मंत्रालय के भीतर डीपीए भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग का समन्वय करता है। यह अनुदान और भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वित्त मंत्रालय बहुपक्षीय सहायता का प्रबंधन करता है और एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान किए गए रियायती ऋणों और लाइन ऑफ़ क्रेडिट का प्रशासनिक निरीक्षण करता है।

भारत के प्राथमिक भागीदार देश दक्षिण एशिया में उसके पड़ोसी देश है। 2009 और 2015 के बीच, भूटान को भारत के द्विपक्षीय विकास सहयोग का 61% प्राप्त हुआ, इसके बाद अफगानिस्तान (9%), श्रीलंका (7%), नेपाल (5%), बांग्लादेश (3%), म्यांमार (2%) और मालदीव (2%) को प्राप्त हुआ । हाल ही में, अफ्रीका के साथ सहयोग बढ़ा है। भारत के विकास सहयोग के मुख्य क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा (हाइड्रो पावर) और सूचना प्रौद्योगिकी है।[3] 1990 के दशक में देश की विदेशी विकास सहायता में काफी वृद्धि हुई और 2004 में महत्वपूर्ण बदलाव आए जब भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) के दूसरे चरण के अंतर्गत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्सिम) के माध्यम से एशिया और अफ्रीका में भागीदार देशों को रियायती ऋण देने का कार्यक्रम शुरू किया। विदेश मंत्रालय (एमईए) के सुझाव पर विकासशील देशों को एलओसी प्रदान किए जाते है, 2020 तक 64 देशों को 30.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 300 से अधिक एलओसी दिए गए। इस राशि का लगभग आधा, 15.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशियाई देशो को दिया गया है। जिसका सबसे बड़ा मूल्य भारत के पड़ोसियों - बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मॉरीशस, मालदीव, म्यांमार और सेशेल्स को जाता है। यह फंड महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्रों को कवर करता है - जैसे रेलवे, सड़के और बंदरगाहो के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी; बिजली उत्पादन और वितरण; कृषि और सिंचाई; विनिर्माण उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षमता निर्माण आदि।[4]

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग

1964 में उद्घाटित, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकी सहायता कार्यक्रम और कोलंबो योजना के तहत तकनीकी सहयोग योजना के साथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया के 161 देशों को कवर करता है। तकनीकी और आर्थिक सहयोग और विदेशी सरकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम मुख्य रूप से एशिया को दिए गए। चुने गए सभी आठ प्राप्तकर्ता देश एशिया में है; जिन्हे 2011 में 529 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इनमें से, भूटान अब तक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है, जिसे 2011 में 387 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए, जो भारत के कुल तकनीकी और आर्थिक सहयोग का 59% है । उसके बाद अफगानिस्तान (59 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और मालदीव (40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का स्थान है। अफ्रीकी देशों (जिनका केवल क्षेत्रीय डेटा उपलब्ध है) को 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले और अन्य क्षेत्रों के देशों को 59 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। सबसे बड़े प्राप्तकर्ता वे देश है जहां प्रतिदिन 1.25 डॉलर से कम पर रहने वाले लोगों की संख्या और दर कम है, हालांकि नेपाल (7.4 मिलियन और 25%) और बांग्लादेश (64.3 मिलियन और 43%) एक अपवाद है। अफगानिस्तान, मंगोलिया और म्यांमार के गरीबी के आंकड़े (पावर्टी डाटा) उपलब्ध नहीं है।[5]

1 FIDC Policy Brief Indian Development Cooperation: A Theoretical and Institutional Frameowkr.pdf (ris.org.in)
2 Overview of India's Development Partnership (mea.gov.in)
3 India's Development Co-operation - OECD
4 Institutional architecture for India's development cooperation: A 2030 vision | ORF (orfonline.org)
5 Investments-to-End-Poverty-Chapter-9-India.pdf (devinit.org)

भारत की अनुदान-सहायता

भारत को पारंपरिक रूप से घरेलू और विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में माना जाता रहा है। लेकिन इसका अपना एक विदेशी सहायता कार्यक्रम भी है जो 1950 और 1960 के दशक में पाया गया। भारत का सहायता कार्यक्रम छोटा था, स्थानीय क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित था और इसे दयाशील के रूप में देखा जाता था। पिछले कुछ वर्षों में, भारत के विदेशी सहायता कार्यक्रम में आकार, केंद्र और रणनीतिक सोच में उल्लेखनीय बदलाव हुए है।[6] 2021-22 में भारत के बजट अनुसार, प्रत्यक्ष विदेशी सहायता ₹18,154 करोड़ (2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।[7] भारत ने 2012-13 में विदेशी सहायता पर 1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए । 2009 के बाद से, विदेशी सहायता सालाना लगभग 3.2 गुना बढ़ गई थी।[8] भारत मानवीय प्रयासों और आपदा राहत में भी काफी सक्रिय है, अक्सर ऋण, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य प्रकार की सहायता देता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार में आपदा राहत में मदद करने वाले राष्ट्र को "द नेबरहुड फर्स्ट रिस्पॉन्डर" भी कहा है। 2016 में विंस्टन चक्रवात के बाद फिजी जैसे देशों को मानवीय सहायता दी गई। हाल ही में, भारत ने मौद्रिक सहायता, भोजन दान और टीकों के वितरण के माध्यम से कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद की है। वैक्सीन की कमी से जूंझ रहे ब्राजील को भारत सरकार से 20 लाख खुराक मिलीं।[9]

2021-22 में भारत के बजट अनुसार
प्रत्यक्ष विदेशी सहायता ₹18,154 करोड़
(2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) थी।

भारत ने 2012-13 में विदेशी सहायता पर
1 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए ।

लाइन ऑफ क्रेडिट[10]

भारत सरकार की इंडियन डेवलपमेंट एंड इकनोमिक असिस्टेंस स्कीम (आईडीईएएस) के तहत एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया के माध्यम से रियायती लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) के रूप में विकास सहायता प्रदान की जाती है। 30.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 300 से अधिक एलओसी 64 देशों को दिए गए है। एलओसी के तहत परियोजनाओं में रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों के माध्यम से परिवहन कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्र जैसे बिजली उत्पादन और वितरण; कृषि और सिंचाई; विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और क्षमता निर्माण शामिल है । अब तक लगभग 300 एलओसी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी है जबकि 260 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित है।

30.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल एलओसी में से 15.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर एशियाई देशों को दिए गए है, जिसमें भारत के निकटतम पड़ोसी देशो को सबसे अधिक मूल्य दिया गया। बांग्लादेश को 7.862 बिलियन अमेरिकी डॉलर, श्रीलंका को 2.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर, नेपाल को 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मॉरीशस को 964.80 अमेरिकी डॉलर, मालदीव को 840 मिलियन अमेरिकी डॉलर, म्यांमार को 538.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सेशेल्स को 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

भारत सरकार के एलओसी के तहत पड़ोस से क्षेत्रीय संपर्क पहल पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये क्षेत्रीय विकास और विकास में तेजी लाने, लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ावा देने और व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करते है।

6 Chanana, Dweep. "India as an Emerging Donor." Economic and Political Weekly, vol. 44, no. 12, 2009, pp. 11–14.
7 Budget 2021: Over Rs 18,000 Crore Allocated For External Affairs Ministry, Rs 7,149 Crore For Foreign Aid (ndtv.com)
8 Despite tempered outlook, BRIC countries stay the course on foreign aid | Devex
9 India's Development Partnership | The Borgen Project
10 Lines of Credit for Development Projects (mea.gov.in)

एलओसी का वर्गीकरण[11]

भारत सरकार इंडियन डेवलपमेंट एंड इकनोमिक असिस्टेंस स्कीम (आईडीईएएस) के तहत एलओसी के प्रसंस्करण के लिए एक वर्गीकरण मानदंड लेकर आई है - निम्न और निम्न मध्य आय (एल एंड एलएमआई) देशों में न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकताएं, निम्न और निम्न मध्यम आय (एल एंड एलएमआई) देशों में न्यूनतम बाध्यकारी रियायती आवश्यकताएं लागू न होना और अन्य विकासशील देशो में भी।

एलओसी के लाभ

एलओसी प्राप्तकर्ता देशों को विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को स्थापित करने में सक्षम बनाता है जैसे कृषि मशीनीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली उत्पादन, बिजली वितरण, चीनी, सीमेंट, मिनी हाइड्रो-प्लांट, परिवहन-रेल और सड़क संरचना आदि । प्राप्तकर्ता देश भारतीय उपकरण और प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सकते है, जो विकासशील देशों में उपयुक्त, अनुकूल और किफायती होते है। एलओसी उन देशों की क्षमता निर्माण में योगदान देता है जहां परियोजनाओं को लागू किया जाता है, भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार के अवसर खुलते है और भारत की साख भी बढ़ती है।[12] विशेष रूप से अफ्रीकी देशों के लिए एलओसी मांग से प्रेरित है और कई अफ्रीकी देशों को उनकी जरूरतों के अनुकूल एक विशेष परियोजना का चयन करने का विकल्प दिया जाता है।[13]

भारतीय विकास सहयोग का प्रक्षेप-पथ

भारत की विकास सहायता योजना के रूप में परिनियोजित किए जा रहे सभी उपकरणों में, एलओसी अन्य देशों को भारत की कुल सहायता का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है।[14] इसने अपनी विशेषताओं को मुख्य रूप से विकसित किया है और यह अलग-अलग पांच स्तरों पर काम करता है, यानि व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) और अनुदान द्वारा विकास सहायता प्रदान करता है । अन्य दक्षिणी देशों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जुड़ाव ने इन पांच तत्वों में व्यापक सहयोग के लिए एक प्रमुख प्रभाव कारक प्रदान किया है, जो आर्थिक विकास के लिए व्यापक सहयोग पर जोर देता है।[15] इसके अलावा, भारतीय विकास सहयोग प्राप्तकर्ता देशों पर कोई शर्त लागू नहीं करता है।[16] हालांकि, इस क्षेत्र में रणनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में भारतीय विकास सहयोग राजनीतिक उपकरण बन गया है।[17]

भारत के विकास सहयोग में संरचना का विकास

संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अपनी स्थापना के बाद से विकास की बहस का केंद्र रहा है। विदेशी सहायता के शुरुआती दिनों में, दाताओं का ध्यान संरचना पर बहुत अधिक था क्योंकि संरचना के लिए अधिकांश वित्त केवल विदेशी अनुदान से ही आ सकता था। जबकि बड़े विकासशील देशों के पास अधिक घरेलू राजस्व था जिसके साथ स्वतंत्रता के बाद के संरचना निवेश को वित्तपोषित किया गया था।[18] इस तरह की आधुनिक विकास सहायता मार्शल योजना के साथ शुरू हुई, जिसके माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन यूरोपीय देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की, जिनकी अर्थव्यवस्थाओं को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नुकसान उठाना पड़ा था।

आज, विकास सहायता कई रूप ले रही है। एक देश दूसरे को प्रत्यक्ष मौद्रिक योगदान के रूप में विकास सहायता की आपूर्ति कर सकता है, अथवा यह अधिक नागरिकों को पानी की आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर सकता है। यह संरचना निर्माण के लिए आवश्यक कौशल सिखाने में भी मदद कर सकता है।[19]

ग्लोबल साउथ में भारत की संरचना परियोजनाएं

भारत नेपाल में पारदी, त्रिशूली और देवीघाट जैसे कई हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विकसित करने के लिए आगे आया है।[20] 2014 तक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत, भारत ने दो जल विद्युत परियोजनाओं को फंड देने की योजना बनाई है।[21] अफगानिस्तान में, सलमा बांध (जिसे अब अफगान-भारत मैत्री बांध कहा जाता है) का उद्घाटन

11 Exim_LoC.pdf (dea.gov.in)
12 Exim Bank Lines of Credit Guidelines (eximbankindia.in)
13 The changing nature of India's Lines Of Credit to Africa | ORF (orfonline.org)
14 India's development partnership: key policy shifts and institutional evolution (ris.org.in)
15 Chaturvedi S. The Development Compact: A Theoretical Construct for South–South Cooperation*. International Studies 2016;53(1):15-43. doi:10.1177/0020881717705927
16 India's development cooperation does not come with any conditions: PM Modi | India News - Times of India (indiatimes.com
17 India's development cooperation – are we getting it right? | ORF (orfonline.org)
18 Addison, T. & Anand, P.Bhayankara (2012) Aid and Infrastructure Financing: Emerging Challenges with a Focus on Africa. WIDER Working Paper 2012/056. Helsinki: UNU-WIDER.
19 What is Development Aid - Foreign Aid & Development | Anera
20 Agreement regarding Hydro-electric Power Project (mea.gov.in)
21 Gangol, Pradeep (January 2014). "Foreign Direct Investment in Nepal's Hydropower Development". Hydro Nepal. 20

2016 में 290-300 मिलियन अमरीकी डालर की राशि से किया गया था। संरचना विकास के लिए 2008 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के बाद, 2011 में, अफ्रीकी देशों को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया । संरचना परियोजनाओं में श्रीलंका को रेलवे परियोजना के लिए 492 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, बेलारूस को बिजली संयंत्र के लिए 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले, जबकि मंगोलिया को आईटी प्रशिक्षण केंद्रों और पशुधन टीकाकरण कार्यक्रमों की स्थापना के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। अफ्रीकी संरचना परियोजनाओं के लिए भारत की प्रतिबद्धता इससे कहीं अधिक है।[22] 2015 में 524 मिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारतीय प्रतिबद्धताओं का सबसे बड़ा हिस्सा परिवहन (513 मिलियन अमेरिकी डॉलर), इसके बाद ऊर्जा (422 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और पानी (262 मिलियन अमेरिकी डॉलर) परियोजनाओं के लिए चला गया।[23]

संरचना परियोजनाओं के आकलन के लिए संकेतक

चूंकि संरचना के लिए ग्लोबल साउथ देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी में आमतौर पर मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए मेगा और बड़ी संरचनाएं[24] शामिल होती है, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतकों का उपयोग कर रहे है जो इन परियोजनाओं की उपयोगिता निर्धारित करने में मदद करेंगे। विशाल संरचना परियोजनाएं (मेगा-इंफ्रास्ट्रक्चर) निर्माण का लोगों के मानवीय, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।[25]

विशाल संरचना परियोजनाओं के कारण होने वाले प्रत्यक्ष प्रभाव निम्नलिखित है:

1. भूमि अधिग्रहण

विशाल परियोजना संचालन के प्रमुख परिणामों में से एक लोगों का उनकी भूमि से विस्थापन है। उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों और सड़कों की स्थापना के लिए स्थानीय समुदायों से भूमि का अधिग्रहण अकेले ही घरों और लोगों की आजीविका के नुकसान के लिए जिम्मेदार रहा है।[26]

2. आजीविका और जीने के तरीके का नुकसान

विशाल संरचना के विकास में केवल भूमि के एक टुकड़े का नुकसान नहीं होता है बल्कि सामुदायिक संबंधों, सामान्य सांस्कृतिक जड़ों का भी नुकसान होता है। कई विशाल संरचना परियोजनाएं ग्लोबल साउथ के उन क्षेत्रों में विकसित की जाती है जहां स्थानीय आबादी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संघर्ष कर रही होती है।[27]

3. वनस्पति, जीव और जलीय जीवन का पतन

विशाल संरचना निर्माण के परिणामस्वरुप वनस्पतियों और जीवों का बड़े पैमाने पर पतन होता है और परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्रों में फैल जाता है। औद्योगिक बहिःस्रावों से बहने वाला जल आपूर्ति से जुड़े जल निकायों को दूषित कर देता है।

4. पुनः स्थापना और पुनर्वास

विशाल संरचना परियोजनाओं को सरकारी अनुमोदन के माध्यम से अधिग्रहित भूमि के नुकसान के लिए जाना जाता है लेकिन लोगों को प्रभावी ढंग से पुनः स्थापित और पुनर्वास करने में विफल रहता है।[28] जीवन के तरीके का नुकसान अन्य क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को अत्यधिक प्रभावित करता है और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है।[29]

---

22 India's development partnership: key policy shifts and institutional evolution (ris.org.in)

23 Connecting Africa: Role of transport infrastructure - tralac trade law centre

24 Mega projects include bridges, tunnels, highways, railways, airports, seaports, power plants, dams, wastewater projects, Special Economic Zones(SEZ), oil and natural gas extraction projects, public buildings, information technology systems, aerospace projects, etc.,

25 OHCHR | Human rights trampled in push to build infrastructure

26 Desai Mihir, "Land Acquisition Law and the Proposed Changes", EPW, Vol. XLVI Nos. 26 & 27, June 25 2011, p. 95

27 Tyagi A. C., "Resettlement and rehabilitation in River Valley Projects" in, Environmental Management in Hydropower and River Valley Projects- Techniques of Management Policy Issues, Case Studies and Application of Scientific Tools, Radhey Shyam Goel, (Ed.), (New Delhi, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, 2000), p. 175.

28 Hari Mohan Mathur and David Marsden, Development Projects and Impoverishment Risks Resettling Project-Afftected People in India, (New Delhi, Oxford University Press, 2000), p.30.

29 Fernandes and Vijay Paranjpye (eds.) (1997) 'Rehavilitation Policy and Law in India: A Right to Livelihood', Indian Social Institute, New Dehli quoted in Murickan, Jose (2003), 'Development-Induced Displacement: Case of Kerala', Rawat Publications, Jaipur.

5. जल प्रदूषण और लवणता

जल प्रदूषण और लवणता बड़े पैमाने पर संरचना निर्माण से उत्पन्न चिंता का एक प्रमुख कारण है। पानी की रासायनिकता में वृद्धि जो सिंचाई के लिए उपयोग की जाती है, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालती है।

6. मुआवजा

भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया में मुआवजे की सही राशि प्रदान करना शामिल है। कई बार, यह मुआवजा प्रभावित समुदायों और समूहों को पर्याप्त रूप से प्रदान नहीं किया जाता है, जिसके कारण उन्हें पुनर्वास में असहनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।[30] [31]

मानव अधिकारों पर विशाल संरचना परियोजनाओं का प्रभाव

मानव अधिकारों पर विशाल संरचना परियोजनाओं का तीन स्तरीय वर्गीकरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है-

क) सूक्ष्म स्तर पर- सबसे गंभीर समस्याएं अक्सर भूमि के अधिग्रहण अथवा संसाधनों के अधिकार से उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि और संसाधन स्वामित्व से इनकार, स्थानांतरण, जबरन कब्ज़ा और पर्याप्त जीवन स्तर तथा आजीविका की हानि होती है। भूमि पर प्रभाव से जैव विविधता का भी नुकसान होता है। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु के खतरों के साथ-साथ निर्माण और संचालन के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा समस्याओं के प्रभाव श्रमिकों और समुदायों के लिए जारी रहते है। यौन हिंसा, मानवाधिकार रक्षकों को धमकी तथा सुरक्षा बलों पर हिंसा अन्य मानवाधिकार प्रभावों में से है। यदि पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के साथ ठीक से योजना नहीं बनाई जाये तो परियोजनाओं के पूर्ण होने पर गंभीर नकारात्मक मानवाधिकार प्रभाव उत्पन्न हो सकते है।

ख) मध्यम स्तर पर - पानी सहित कुछ सामाजिक सेवाओं तक पहुंच और उपलब्धता पर मानवाधिकार कानून स्पष्ट रूप से संरक्षित है। बार-बार या दर में अत्यधिक वृद्धि या भुगतान करने में असमर्थता के कारण सेवा से इनकार करना मानवाधिकार कानून का उल्लंघन हो सकता है। आम तौर पर, निजी क्षेत्र में सेवाओं की वहनीयता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की कमी होती है, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए नियामक सुधार, कमजोर व्यक्तियों और समुदायों को अनौपचारिक सेवाओं से काट सकते है।

ग) विस्तृत स्तर पर - राज्यों और अन्य कर्ताओ के कार्य और गलतियाँ करदाताओं और सामान्य जनता को विभिन्न नकारात्मक तरीकों से प्रभावित करती है। उदाहरणों के लिए - खराब डिजाइन, प्रक्रिया और नियोजन निर्णय, परियोजना के लिए पर्यावरण और मानवाधिकार प्रभाव मूल्यांकन करने में विफलता, संचयी, सीमा उल्लंघन और रणनीतिक स्तरों के साथ-साथ वित्तीय और वित्तीय कुप्रबंधन शामिल है, जो अधिक ऋण और सार्वजनिक सेवाओं का समापन करके सार्वजनिक संसाधनों को बेकार कर सकते है और वित्तीय बोझ का कारण बन सकते है। खरीद के फैसले भी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण मानवाधिकारों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को बड़ा सकते है।[32] [33]

संरचना की सामाजिक-आर्थिक उपयोगिता को मापने के लिए प्रयोग किये जाने वाले सामान्य संकेतक एसडीजी 9 में उपलब्ध है ।

"लचीला संरचना निर्माण, स्थायी औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा"

- सभी के लिए वहनीय और समान पहुंच पर ध्यान देने के साथ, आर्थिक विकास और मानव कल्याण को सहयोग करने के लिए दीर्घकालीन, विश्वसनीय, लचीली और उत्तम संरचना निर्माण, जिसमे क्षेत्रीय और सीमा पार की संरचना शामिल है।
- समावेशी और दीर्घकालीन औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और 2030 तक राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना और न्यूनतम विकसित देशों में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करना।

30 Hari Mohan Mathur and David Marsden, Development Projects and Impoverishment Risks Resettling Project-Afftected People in India, (New Delhi, Oxford University Press, 2000), p.30.
31 Burrows, P. (1991). Compensation for Compulsory Acquisition. Land Economics, 67(1), 49-63. doi:10.2307/3146485
32 HBS-OHCR, The Other Infrastructure Gap SR_OHCHR-Kurzfassung-en_Futura_Web.indd
33 Microsoft Word - OHCHR Baseline Study Revised Oct 22 2017

- छोटे पैमाने के औद्योगिक और अन्य उद्यमों में, विशेष रूप से विकासशील देशों में, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना, जिसमें किफायती ऋण शामिल है और मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों में उनका एकीकरण करना।
- 2030 तक, संरचना सुधार और उद्योगों को टिकाऊ बनाने के लिए पुनःसंयोजन, संसाधन-उपयोग दक्षता में बढ़ोतरी और स्वच्छ तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों और औद्योगिक प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक अपनाने के साथ ही अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार सभी देश कार्रवाई कर रहे है।[34]

मानव अधिकारों पर संरचना के प्रभाव को मापने के लिए उपलब्ध मानक-

- *उत्तम संरचना निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे-शिमा सिद्धांत*[35]

सिद्धांत 1:	प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद और साइबर हमलो के खिलाफ जीवन-चक्र लागत के साथ सुरक्षित, लचीले, प्रभावी और विश्वसनीय संचालन तथा आर्थिक दक्षता सुनिश्चित करना।
सिद्धांत 2:	स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता तथा जानकारी का हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
सिद्धांत 3:	सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को संबोधित करना।
सिद्धांत 4:	राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पहलू सहित आर्थिक और विकास रणनीतियों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
सिद्धांत 5:	पीपीपी के माध्यम से प्रभावी संसाधन जुटाने को बढ़ाना देना।

- *विश्व बैंक/आईएफसी प्रदर्शन मानक/एमडीबी सुरक्षा नीतियां*[36]

विश्व बैंक का नया एन्वाइरोमेंटल एंड सोशल फ्रेमवर्क (ईएसएफ) 2018 में शुरू होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के नए निवेश ऋण पर लागू होगा। हालांकि 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' में व्यक्त मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए सहयोग, दीर्घकालीन विकास और स्वदेशी लोगों के मानवाधिकारों के लिए सम्मान का घोषित उद्देश्य विश्व बैंक के दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो बैंक के मौजूदा सुरक्षा उपायों में प्रतिबद्ध है।

- *ईएचएस सामान्य दिशानिर्देश*[37]

निजी क्षेत्र विश्व बैंक समूह के ईएचएस दिशानिर्देशों को वास्तविक अंतरराष्ट्रीय उद्योग मानकों के रूप में लागू करता है। सामान्य दिशानिर्देश हवा और पानी की गुणवत्ता के मुद्दों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, और सभी क्षेत्रों के लिए आम तौर पर लागू होने वाली प्रतिबन्ध गतिविधियों को कवर करते है। इसके अलावा, निम्नलिखित संरचना क्षेत्रों को विशेष रूप से कवर किया गया है: एयरलाइंस; हवाई अड्डे; कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद टर्मिनल; गैस वितरण तंत्र; स्वास्थ्य सेवा सुविधाये; बंदरगाह, और टर्मिनल; पावर (इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन; जियोथर्मल पावर जनरेशन; थर्मल पावर; और पवन ऊर्जा); रेलवे; खुदरा पेट्रोलियम नेटवर्क; शिपिंग'; दूरसंचार; पथकर मार्ग; पर्यटन और आतिथ्य विकास; अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं; और पानी तथा स्वच्छता। हालांकि, जलविद्युत परियोजनाओं पर कोई दिशानिर्देश नहीं है, और इन दिशानिर्देशों के तहत कोयला बिजली परियोजनाएं प्रतिबंधित नहीं है।

- *बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर ओईसीडी दिशानिर्देश (एमएनई दिशानिर्देश) और सामान्य दृष्टिकोण:*

हालांकि यह संरचना के लिए विशिष्ट नहीं है, एमएनई दिशानिर्देशों में व्यवसाय के जिम्मेदार संचालन के लिए आवश्यकताओं के व्यापक सेट शामिल है, और इसमें प्रकटीकरण, मानव अधिकार, रोजगार और औद्योगिक संबंध, पर्यावरण, रिश्वतखोरी का विरोध और उपभोक्ता हितों पर अध्याय शामिल है। मानवाधिकार अध्याय स्पष्ट रूप से यूएनजीपी के साथ संरेखित है।[38]

34 https://sdgs.un.org/goals/goal9
35 G7 Ise-Shima Principles for Promoting Quality Infrastructure Investment (mofa.go.jp)
36 https://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/The-World-Bank-Environmental-and-Social-Framework.pdf
37 Environmental, Health, and Safety Guidelines (ifc.org)
38 Guidelines for MNEs - Organisation for Economic Co-operation and Development (oecd.org)

- *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भूमि, मत्स्य पालन और वन के कार्यकाल के जिम्मेदार संचालन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश*

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा शुरू किए गए इन स्वैच्छिक दिशानिर्देशों को कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों और स्वयं सेवी संस्थानों का सहयोग प्राप्त है। स्वैच्छिक दिशानिर्देशों का उद्देश्य भूख और गरीबी को मिटाने के साधन के रूप में भूमि, मत्स्य पालन और जंगलों तक सुरक्षित कार्यकाल के अधिकारों और समान पहुंच को बढ़ावा देना है, जिससे दीर्घकालीन विकास और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि हो। वे संरचना परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण और पहुंच में सहायक मार्गदर्शन प्रदान करते है।[39]

बांग्लादेश-भारत रामपाल पावर स्टेशन

वर्तमान में रामपाल पावर स्टेशन बांग्लादेश के खुलना में बागेरहट जिले के रामपाल उपजिला में 1320 मेगावाट का कोयला आधारित निर्माणाधीन पावर स्टेशन है। इस ऊर्जा संयंत्र का निर्माण 1834 एकड़ से अधिक भूमि पर किया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन सुंदरवन जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है से 14 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड[40] [41] (बीआईएफपीसीएल) द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो भारत के स्वामित्व में राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और बांग्लादेश के बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच 50 के अनुपात का संयुक्त उद्यम है। बीआईएफसीपीएल ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2X660MW) की स्थापना के लिए भेल (बीएचईएल) को 1.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ईपीसी अनुबंध प्रदान किया।[42]

परियोजना विवरण

रामपाल के कोयला ऊर्जा संयंत्र की लागत 2 बिलियन अमरीकी डालर है। आई जे ग्लोबल के अनुसार, इस परियोजना का ऋण-इक्विटी अनुपात 80:20 है। दोनो कंपनियों बीपीडीबी और एनटीपीसी के पास बीआईएफपीसीएल वाणिज्यिक संयुक्त उद्यम के स्वामित्व का समान हिस्सा है, और इस परियोजना के लिए समान रूप से 20% भागीदारी (कुल मिलाकर 400 मिलियन अमरीकी डालर) प्रदान करते है। शेष 80% का ऋण इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है: भारतीय निर्यात ऋण एजेंसी 1.6 बिलियन अमरीकी डालर के साथ परियोजना का वित्तपोषण कर रही है। बांग्लादेशी सरकार ने परियोजना लागत की 70% राशि की सार्वभौमिक गारंटी जारी की है।

विदेशी ऋण देने वाले समूहों को निवेश लौटाने का आश्वासन देने के लिए। इसके अतिरिक्त, संयुक्त उद्यम कंपनी को 15 साल तक कर मुक्ति का लाभ मिलेगा। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने परियोजना को वित्त देने से इनकार कर दिया था, इसलिए बीआईएफपीसीएल ने निर्यात ऋण एजेंसी (ईसीए) से ऋण लेने का फैसला किया जिसमें उच्च ब्याज दरें शामिल थी। इससे पहले, तीन फ्रांसीसी बैंकों, क्रेडिट एग्रीकोल, बीएनपी परिबास और सोसाइटी जेनरेल ने कहा था कि वे संयंत्र में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि यह पाया गया था कि प्रस्तावित परियोजना न्यूनतम पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों को पूरा करने में विफल थी।[43]

आर्थिक क्षमता

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालाइसिस की 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार, रामपाल पावर स्टेशन में बांग्लादेश और भारत से कई सब्सिडी के बावजूद, बिजली के उत्पादन की लागत बांग्लादेश में औसत बिजली की लागत से 32% अधिक होगी। वित्तीय विशेषज्ञ दल का तर्क है कि सार्वजनिक सब्सिडी में परियोजना की लागत 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है: "पहला, भारतीय एक्जिम बैंक द्वारा बाजार-दर से नीचे का ऋण, भारतीय करदाताओं द्वारा बांग्लादेशी उपभोक्ताओं को प्रभावी रूप से भुगतान की गई 988 मिलियन अमेरिकी डॉलर सब्सिडी का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, बांग्लादेश सरकार को संयंत्र के लिए 15 साल की आयकर छूट का प्रस्ताव कर रहा है, जिसका मूल्य 936 मिलियन अमेरिकी डॉलर की छूट है। तीसरा, बांग्लादेश संयंत्र को कोयले की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव ड्रेजिंग आयोजित करके 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक प्रभावी वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगा।[44]

सिविल सोसाइटी की चिंता

यह परियोजना कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है।[45] सुंदरबन से 14 किलोमीटर की दूरी पर संयंत्र का स्थान, एक मूलभूत शर्त का उल्लंघन करता है जो कहता है कि ऐसी परियोजनाएं पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर होनी

39 Voluntary Guidelines on Tenure | Governance of Tenure | Food and Agriculture Organization of the United Nations (fao.org)
40 Bangladesh, India sign Rampal power plant construction agreement | bdnews24.com
41 BIFPCL
42 Bhel bags NTPC's Bangladesh project - The Economic Times (indiatimes.com)
43 pdf (banktrack.org)
44 Risky-and-Over-Subsidised-A-Financial-Analysis-of-the-Rampal-Power-Plant-_June-2016.pdf (ieefa.org)
45 Bangladesh Power Plant Struggle Calls for International Solidarity | HuffPost

चाहिए।[46] पर्यावरण कार्यकर्ताओं का तर्क है कि रामपाल स्टेशन का प्रस्तावित स्थान रामसर कन्वेंशन के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। रामसर कन्वेंशन, जिसमें बांग्लादेश एक हस्ताक्षरकर्ता है, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। सुंदरवन रामसर की अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में है।[47]

सुंदरबन क्षेत्र में ऊर्जा संयंत्र से होने वाले उत्सर्जन से पारिस्थितिक जलवायु में भारी बदलाव आएगा। इसी तरह, ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले पानी से नदी के पानी का तापमान बढ़ जाएगा (दक्षिण एशियाई मानवाधिकार, 2015)। यह स्पष्ट है; निर्माण के दौरान और ऊर्जा उत्पादन के दौरान यह भारी ध्वनि प्रदूषण करेगा।[48] पर्यावरण और पारिस्थितिक विशेषज्ञों द्वारा की गई भविष्यवाणी यह है कि संयंत्र कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को छोड़ेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों और, सबसे महत्वपूर्ण, सुंदरबन के वातावरण को गंभीर नुकसान होगा।[49]

भारतीय सिविल सोसाइटी से सहयोग

भारत के प्रमुख जन आंदोलनों और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों ने आज बांग्लादेश में भारत सहयोगी रामपाल ऊर्जा परियोजना के विरूद्ध संघर्ष के लिए अपना सहयोग और एकजुटता व्यक्त की, राष्ट्रीय समिति द्वारा विरोध के वैश्विक दिवस के अवसर पर तेल-गैस-खनिज संसाधन शक्ति और पोर्ट की रक्षा के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत सरकार से परियोजना से निकलने का आग्रह करते हुए, बयान में कहा गया, "भारत के एनटीपीसी का संयुक्त रूप से परियोजना में स्वामित्व होने के साथ, भेल आपूर्ति उपकरण और इंडियन एक्ज़िम बैंक वित्त प्रदान करते है, इस परियोजना में भारत का पदचिह्न बहुत बड़ा है, जो इसमें दो पड़ोसी देशों के बीच असंतोष को कायम रखने की क्षमता रखता है।[50]

रामपाल पावर स्टेशन का प्रभाव

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव	मध्यम स्तर पर प्रभाव	विस्तृत स्तर पर प्रभाव
सुंदरबन में रहने वाले समुदायों से जबरदस्ती जमीन का अधिग्रहण	श्वसन रोगों के लिए कारक	परियोजना के डिजाइन और योजना में गैर-पारदर्शिता
सुंदरवन के परिधीय क्षेत्रों की जैव विविधता पर प्रभाव	सुंदरवन पर निर्भर स्थानीय समुदायों की आजीविका को खतरा	अभी तक कोई ऋण समस्या की सूचना नहीं है

भूटान-भारत जलविद्युत परियोजनाएं

जलविद्युत परियोजनाएं: विकास सहायता और सहयोग

भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग 1961 में जलधाका समझौते पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ। जलधाका परियोजना पश्चिम बंगाल में भारत-भूटान सीमा के भारत की ओर स्थित है। जलधाका जलविद्युत संयंत्र में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा दक्षिणी भूटान को निर्यात किया गया था। भारत-भूटान जल-संबंधों के इतिहास में एक ऐतिहासिक विकास 1987 में 336 मेगावाट चुखा जलविद्युत परियोजना (सीएचपी) के चालू होने के साथ हुआ।

भूटान की पहली विशाल ऊर्जा परियोजना, सीएचपी को भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान और 40 प्रतिशत ऋण के साथ पूरी तरह से वित्त पोषित किया गया था, जो कमीशन के बाद 15 वर्षों की अवधि में 5 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय था। एक परियोजना की सफलता ने विश्वास, आर्थिक व्यवहार्यता और साझा लाभों के आधार पर अन्य परियोजनाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया । भारत और भूटान के बीच सबसे बड़ी संयुक्त परियोजनाओं में से एक 1,020 मेगावाट की ताला जलविद्युत परियोजना को भी भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान और 40 प्रतिशत ऋण के साथ पूरी तरह से वित्तपोषित किया गया था। दोनों देशों ने जुलाई 2006 में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर (एचईपी) के क्षेत्र में भारत में सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए है, जो जलविद्युत के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूपरेखा तैयार करता है।[51] [52]

46 Save The Sundarban: Rampal Power Station (Proposed)
47 A new power plant could devastate the world's largest mangrove forest - The Washington Post
48 Why are People Opposing Ramp (isdesr.org)
49 More reasons to stop Rampal power plant (archive.org)
50 Prominent Indian Groups Support Struggle against Rampal Project – Centre for Financial Accountability (cenfa.org)
51 Bhutan-India Hydropower Relations – Royal Bhutanese Embassy New Delhi (mfa.gov.bt)
52 MEA | India and Neighbours | Bhutan

भारत-भूटान एचईपी परियोजना विवरण

चुखा जलविद्युत परियोजना, या चुखा जलविद्युत, भूटान की पहली मेगा पावर परियोजना थी। जिसका निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ और 1986 में उसकी कमीशनिंग हुई, और सरकार ने 1991 में इसका पूर्ण नियंत्रण ले लिया । गर्मियों के दौरान, यह संयंत्र थिम्फू और फुंटशोलिंग के बीच मध्यवर्ती चुखा जिले में वांगछु नदी के प्रवाह से चार टर्बाइनों से 336 मेगावाट उत्पन्न करता है। परियोजना की लागत 2.46 बिलियन एनयू है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित की गई है, अनुदान के तहत 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत ऋण 5 प्रतिशत ब्याज पर पंद्रह साल लिए । 2005 और 2006 के बीच, अकेले चुखा ने भूटान के कुल राजस्व में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।[54]

ताला जलविद्युत परियोजना भारत और भूटान के बीच अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त परियोजना है, जो 4865 मिलियन kWh/वर्ष उत्पन्न करती है। ताला पश्चिमी भूटान में चुखा द्ज़ोंगखग में स्थित है, जो हिमालय में एक छोटा सा राज्य है। रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना का प्रबंधन ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (THPA) द्वारा किया जा रहा है। यह वांगचू नदी पर स्थित है और 860 मीटर पर, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उच्च स्तर परियोजना है।[55]

पुनात्सांगछु-I एक 1200 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो पश्चिमी भूटान में वांगड्यू फोडरंग ज़ोंगखग (जिला) में पुनात्सांगछु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसकी अनुमानित क्षमता एक औसत वर्ष में 5700 मिलियन यूनिट बिजली है। पुनात्सांगछु-I एचईपी का निर्माण नवंबर 2008 में 3514.8 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से शुरू किया गया था। जुलाई 2016 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए 9375.58 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी। परियोजना की भौतिक प्रगति, 31 दिसंबर 2018 तक 85.10% है। अब तक, भारत सरकार ने परियोजना प्राधिकरण को 7629.3 करोड़ रुपये दिए ।

परियोजना को नवंबर 2016 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, बांध स्थल पर दाहिने किनारे के खिसकने के कारण, जो जुलाई 2013 में हुआ था, परियोजना के चालू होने में देरी हो रही है। PHPA प्रबंधन द्वारा स्थिरीकरण के उपाय किए गए है और परियोजना अधिकारियों के वर्तमान प्रक्षेपण के अनुसार परियोजना के 2022 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।[56]

पुनात्सांगछु-द्वितीय एक 1020 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना है जो पश्चिमी भूटान में वांगड्यू फोडरंग ज़ोंगखग में पुनात्सांगछु नदी पर स्थित है। इसकी अनुमानित क्षमता एक औसत वर्ष में 4357 मिलियन यूनिट बिजली है। पुनात्सांगचु-द्वितीय एचईपी का निर्माण दिसंबर 2010 में 3777.8 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर शुरू किया गया था। अब तक, भारत सरकार ने परियोजना प्राधिकरण को 5668.723 करोड़ रुपये दिए है। परियोजना को दिसंबर 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।[57]

मंगदेछु एक 720 मेगावाट, रन-ऑफ-द-रिवर योजना है जो मध्य भूटान में ट्रोंगसा ज़ोंगखग (जिला) में मंगदेछु नदी पर स्थित है। 95% मशीन उपलब्धता के साथ परियोजना से वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 2925.25 मिलियन यूनिट होगा। मंगदेछु जलविद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर भारत सरकार और भूटान की रॉयल सरकार के बीच 30 अप्रैल 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। सितंबर 2017 को, भारत सरकार ने 4672.38 करोड़ रुपये की परियोजना के दूसरे संशोधित लागत अनुमान (आरसीई) को मंजूरी दी (मार्च 2016 मूल्य स्तर पर)।[58]

निर्माण के पूर्व चरणों में अन्य एचईपी[59]

- बुनाखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट 180 मेगावाट, भूटान के चुखा जिले में बुनाखा गांव के पास स्थित है, मौजूदा चुखा के 325 किलोमीटर अपस्ट्रीम को 70:30 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया है। भागीदारी को टीएचडीसी लिमिटेड, एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और डीजीपीसी, एक भूटानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बीच समान रूप से साझा किया गया है। डीजीपीसी के हिस्से के निर्माण पूर्व चरण में 14 बाँध परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वित्तपोषित किया गया है।
- भूटान के चुखा जिले में वांगचु नदी पर वांगचू जलविद्युत संयंत्र 570 मेगावाट, नदी योजना का संचालन 70:30 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया । भागीदारी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एसजेवीएन लिमिटेड और भूटानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डीजीपीसी के बीच समान रूप से साझा की गई है। परियोजना में डीजीपीसी की भागीदारी का हिस्सा अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

53 Agreement on Chukha Hydro-Electric Project (mea.gov.in)
54 Issue Brief Medha 7 Oct 2011.pmd (idsa.in)
55 Tala Hydroelectric Project - Power Technology | Energy News and Market Analysis (power-technology.com)
56 Embassy of India Thimphu, Bhutan (indembthimphu.gov.in)
57 Ibid
58 Ibid
59 Working_Paper_384.pdf (icrier.org)

- चमकरचू नदी पर चमकरचू जलविद्युत संयंत्र 770 मेगावाट, नदी योजना का संचालन 70:30 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया है । भागीदारी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड और भूटानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम डीजीपीसी के बीच समान रूप से साझा किया गया है। परियोजना में डीजीपीसी की भागीदारी का हिस्सा अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
- दगाचू जलविद्युत परियोजना 126 मेगावाट, रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना, भूटान के दगाना जिले में स्थित, दुनिया की पहली सीमा पार सीडीएम परियोजना है, भूटान के जलविद्युत क्षेत्र में पहला पीपीपी उद्यम 60:40 के ऋण भागीदारी अनुपात द्वारा वित्तपोषित किया गया है - डीजीपीसी (59%), टाटा पावर कंपनी (26%) और भूटान के एनपीपीएफ (15%) के बीच साझेदारी। एडीबी और आरजेडबी, ऑस्ट्रिया द्वारा ऋण प्रदान किए गए है।

भारत द्वारा सहायता प्राप्त एचईपी पर चिंताएँ

भूटान की मजबूत पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण व्यवस्था के बावजूद, भारतीय एजेंसियों द्वारा किए गए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के संबंध में अनियमितताएं हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिए जाते है जो हमेशा पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं होते है। उदाहरण के लिए, पुनात्सांगछु-I (1200MW) और II (1020MW) बिजली परियोजनाओं के निर्माण ने कथित तौर पर लुप्तप्राय सफेद पेट वाले बगुले के आवास को खतरे में डाल दिया है। जबकि इन पक्षियों के लिए कृत्रिम आवास बनाने के प्रयास किए जा रहे है, तथ्य यह है कि उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे है, और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र कमजोर बना हुआ है। इसके अलावा, सभी बिजली परियोजनाओं ने स्थानीय भूटानी अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं दिया है। उल्लेखित साक्ष्य बताते है कि यह प्रमुख भारतीय कंपनियां है जिन्हें परियोजना कार्य करने के लिए उप-अनुबंधित किया जाता है, जो अक्सर भारतीय श्रम पर निर्भर होती है।[60]

सस्ती बिजली की आपूर्ति

सबसे पहले, भूटानी शिकायत करते है कि भारत भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं से सस्ती बिजली खरीदता है। उदाहरण के लिए, 2017 में, भारत द्वारा ताला जलविद्युत परियोजना से जलविद्युत के आयात पर टैरिफ दर 1.80 भूटानी नगुलट्रम (बीटीएन) [0.03 अमेरिकी डॉलर] प्रति यूनिट थी। यह भारत में घरेलू बाजार मूल्य से काफी नीचे था जो प्रति यूनिट ▯7 से ▯8 (लगभग 15 से 16 सिंगापुर सेंट) था।[61] जुलाई 2017 में, भूटान ने चुखा जलविद्युत परियोजना से शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव रखा। आखिरी बढ़ोतरी 2014 में की गई थी जब टैरिफ दर बीटीएन 2 प्रति यूनिट (0.04 अमेरिकी डॉलर) से बढ़ाकर बीटीएन 2.25 (0.045 अमेरिकी डॉलर) प्रति यूनिट कर दी गई थी।[62]

एचईपी के लिए बढ़ता कर्ज

जलविद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में देरी को लेकर भूटान में चिंता है। भारत द्वारा भूटान को दिए जाने वाले ऋण में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है जो देश के लिए ऋण में वृद्धि करता है।[63] [64] भूटान के रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, "जून 2014 तक, भारतीय ऋण भूटान के कुल ऋण का 64 प्रतिशत था और जल विद्युत ऋण कुल ऋण का 83.4 प्रतिशत था। रुपये में मूल्यवर्ग के जलविद्युत ऋण पर वास्तविक ब्याज भुगतान 2014 में ▯1.4 बिलियन (28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था और तीन चल रही जलविद्युत परियोजनाओं (पुणत्संगछु - I, पुनात्संगछु - द्वितीय और मंगदेछु) पर लगभग ▯3.6 बिलियन रुपये की राशि अर्जित की गई थी (70 मिलियन अमेरिकी डॉलर)।[65]

एचईपी के लिए ईआईए की कमी

भूटान में, वन और उद्यान सेवा विभाग देश की पारिस्थितिक देखभाल करता है। एक नियम के रूप में, किसी भी जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) परीक्षण को पास करना होता है। भूटान में, ईआईए उन परियोजनाओं के लिए नहीं किया गया था जिनका निर्माण 2000 से पहले

60 India's Hydropower Investments in Bhutan: Environmental Impacts and the Role of Civil Society | Center for the Advanced Study of India (CASI) (upenn.edu)

61 "More than Doklam Issue, Bhutan is worried about hydropower deficits", The Indian Express, 26 July 2018

62 "Bhutan to supply hydropower to Bangladesh via India", Outlook, 2 July 2017. https://www.outlook india.com/news-scroll/bhutan-to-supply-hydropower-to-bangladesh-via-india/1090541

63 Hydropower debt, Delays biggest challenge in ties with India, say Bhutan officials', Suhasini Haider, 6 September 2017, The Hindu, http://www.thehindu.com/news/national/hydropower-debt-delays-biggestchallenge-in-ties-with-india-say-bhutan-officials/article19630701

64 Vasudha Foundation, 'A Study of the India-Bhutan Energy Cooperation Agreements and the Implementation of Hydropower Projects in Bhutan',

65 "Royal Monetary Authority of Bhutan, Government of Bhutan, Annual Report 2016-17" https://www.rma. org.bt/RMA%20Publication/Annual%20Report/annual%20report%20%202016-2017.pdf.

शुरू हुआ था। इसलिए, चुखा, कुरिचु और ताला जैसी जलविद्युत परियोजनाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था। पुनात्सांगछु-I, पुनात्संगछु-द्वितीय और मंगदेछु के परियोजना अधिकारियों ने ईआईए का संचालन किया था लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।[66]

प्रभाव विश्लेषण

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव	मध्यम स्तर पर प्रभाव	विस्तृत स्तर पर प्रभाव
जबरन अधिग्रहण का कोई मुद्दा दर्ज नहीं किया गया	स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रिपोर्ट नहीं की गईं	बढ़ते कर्ज की समस्या
जैव विविधता पर प्रभाव[5]	रोजगार में कोई खास वृद्धि नहीं[6]	सीमा पार पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव[7]

म्यांमार-भारत कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट

कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट (केएमटीटी) परियोजना भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच सहयोग से बनी थी। यह परियोजना बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और राजमार्गों के एक बहु-मॉडल नेटवर्क के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार और म्यांमार को मिजोरम से जोड़ती है। यह न केवल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश का दूसरा बिंदु खोलेगा, बल्कि म्यांमार को प्रमुख भारतीय बंदरगाहों से जोड़कर भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक संबंधों में भी सुधार करेगा। आवश्यक संरचना के साथ, कार्गो को कोलकाता से मिजोरम पहुंचने में लगभग 3-4 दिन कम लगेंगे और इससे 950 किमी की यात्रा कम होगी।[67]

विदेश मंत्रालय (एमईए) एवं भारत सरकार ने अप्रैल 2008 में म्यांमार के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक फ्रेमवर्क समझौता किया। 2003 में बना फ्रेमवर्क समझौता भारतीय सलाहकार मेसर्स राइट्स द्वारा तैयार म्यांमार के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर आधारित है। कोलकाता (निकटतम भारतीय बंदरगाह / वाणिज्यिक केंद्र) और मिजोरम वर्तमान कार्यान्वयन कार्यक्रम के अनुसार (2009 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन घटकों के लिए डीपीआर के संशोधन के बाद) में निम्नलिखित खंड शामिल है।[68]

विस्तार	साधन	दूरी
कोलकाता से म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह	नौपरिवहन	539 किमी
सित्तवे से पलेटवा (कलादान नदी)	अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी)	158 किमी
पलेटवा से भारत-म्यांमार सीमा (म्यांमार में)	सड़क	110 किमी
एनएच 54 (लॉगटलाई) की सीमा (भारत में)	सड़क	100 किमी

प्रमुख परियोजना घटक

- पोर्ट और आईडब्ल्यूटी घटक
- ड्रेजिंग सहित सितवे में एक एकीकृत बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनल का निर्माण।
- सितवे से पलेतवा (158 किमी) तक कलादान नदी के किनारे नौपरिवहन चैनल का विकास।
- पलेतवा में एक आईडब्ल्यूटी - हाईवे ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण।
- सितवे और पलेटवा के बीच कार्गो के परिवहन के लिए 6 आईडब्ल्यूटी बार्ज (300 टन क्षमता) का निर्माण।
- राजमार्ग घटक

66 Working-Paper-No.-309-India-Bhutan-Hydropower-Projects.pdf (nus.edu.sg)
67 Kaladan Project: Looking East for Economic Development - Essar
68 Ministry of Development of North Eastern Region, North East India (mdoner.gov.in)

- पलेटवा से भारत-म्यांमार सीमा तक 110 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण। [एजेंसी (मैसर्स इरकॉन) विदेश मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित किए जा रहे सड़क घटक को निष्पादित करने के लिए]

कार्यान्वयन ढांचा

- भारतीय पक्ष से विदेश मंत्रालय नोडल एजेंसी है ।
- म्यांमार की ओर से विदेश मंत्रालय (एमएफए) नोडल एजेंसी है।
- फ्रेमवर्क समझौता और दो प्रोटोकॉल (ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट पर प्रोटोकॉल और रखरखाव पर प्रोटोकॉल) के साथ दोनों पक्षों द्वारा 2 अप्रैल 2008 को हस्ताक्षर किए गए।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को विदेश मंत्रालय और आईडब्ल्यूएआई के बीच दिनांक 19.3.2009 के समझौते के तहत पीडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। पीडीसी के रूप में आईडब्ल्यूएआई की जिम्मेदारी वर्तमान में पोर्ट और आईडब्ल्यूटी घटकों के कार्यान्वयन के लिए है।[69]

परियोजना विवरण

मई 2018 तक, भारत ने भारत के भीतर 100 किमी (62 मील) 4-लेन आइजोल-ज़ोरिनपुई राजमार्ग और म्यांमार के भीतर 2 किमी (1.2 मील) ज़ोरिनपुई-कालेतवा 2-लेन राजमार्ग के लिए सभी अनुबंधों किये, जिसे 2019 में पूरा किया जाएगा। हालाँकि, भारत द्वारा उजागर की गई कुछ तार्किक चुनौतियों के बावजूद सित्तवे बंदरगाह का संचालन किया गया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार परियोजना अंतिम चरण में है और यह म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित नहीं होगी।[71]

लाभ

यह मल्टी मॉडल परियोजना बहुआयामी है। जलमार्ग और सड़क दोनों के शामिल होने से परिवहन की दूरी और लागत में कमी आएगी और अन्य देशों के साथ भारत के व्यापार का विस्तार होगा। परियोजना की सबसे बड़ी क्षमता पूर्वोत्तर के विकास में निहित है, जहां पूर्वोत्तर भारत से माल को भारत में अन्य बंदरगाहों से रोडवेज के माध्यम से ले जाने के बजाय सीधे समुद्र के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार सिटवे बंदरगाह को बड़े मालवाहक जहाजों को संभालने में सक्षम बनाने के लिए म्यांमार का पुनर्निर्माण कर रही है। वर्तमान में 2000-3000 टन के जहाजों को संभालने वाला बंदरगाह 20000 टन के जहाजों की क्षमता को संभालने के लिए विकसित किया जा रहा है। परियोजना के लिए लगभग 134 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करते हुए, भारत दिसंबर 2018 में बंदरगाह और अंततः अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल सौप रहा है।[72]

कनेक्टिविटी बढ़ोतरी के अलावा, कलादान मल्टी-मॉडल परियोजना संभावित रूप से स्थानीय आर्थिक विकास के माध्यम से आंतरिक और साथ ही सीमा पार सुरक्षा की बेहतरी सहित अन्य लाभ प्रदान करेगी।[73]

कलादान परियोजना में स्थानीय लोगों के लिए कई लाभ प्रदान करने की क्षमता है, जैसे:

- बेहतर परिवहन संरचना
- स्थानीय किसानों और उत्पादकों के लिए व्यापार के अवसरों में वृद्धि
  खाद्य कीमतों में कमी और भोजन तक बेहतर पहुंच
- परियोजना निर्माण और रखरखाव में रोजगार के अवसर
- स्थानीय लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए आर्थिक विकास[74]

परियोजना से उभरती चिंताएं

उदाहरण के लिए, कलादान आंदोलन, सिविल सोसाइटी संगठनों और पर्यावरण समूह का एक छत्र समूह, में परियोजना के कार्यान्वयन में अस्पष्टता के लिए भारत की आलोचना की । स्थानीय समुदायों को स्पष्ट रूप से परियोजना के प्रभाव के बारे में परामर्श या सूचित नहीं किया गया था। उन्हें परियोजना के लाभों में शामिल नहीं

69 Ibid
70 India ramps up Myanmar ties to gain foothold in ASEAN | The Myanmar Times (mmtimes.com)
71 India-Myanmar Kaladan project in final stages: Jaishankar - The Hindu
72 From Look East to Act East: A review of Kaladan Multi-Modal Transport Project - Centre for Public Policy Research (CPPR)
73 India to provide debt service relief to Myanmar under the G20 initiative - The Economic Times (indiatimes.com)
74 Inside_Kaladan Movement Briefer_English [2].indd (burmariversnetwork.org)

किया जा रहा है और मजदूरी के संबंध में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कार्यकर्ता कलादान परियोजना के पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव और स्थानीय आजीविका पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर भी ध्यान आकर्षित कर रहे है।[75] कलादान परियोजना में स्थानीय समुदायों पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी क्षमता है, जैसे:

- परियोजना निर्माण के दौरान जबरन श्रम का उपयोग
- भूमि की जब्ती और जबरन निष्कासन
- आजीविका में व्यवधान और नुकसान
- बर्मा सेना के सैनिकों की उपस्थिति में वृद्धि
- आवाजाही की स्वतंत्रता और परिवहन तक पहुंच पर प्रतिबंध
- अवैध कराधान और जबरन वसूली
- प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण
- स्वदेशी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन[76]

हालांकि, ऐसे कई उदाहरण है जहां भारत ने स्थानीय प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है और परियोजना से प्रभावित समुदायों के साथ समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है।[77]

कलादान एमएमटी परियोजना का प्रभाव विश्लेषण

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव	मध्यम स्तर पर प्रभाव	विस्तृत स्तर पर प्रभाव
परियोजना के विकास के लिए स्थानीय समुदायों से भूमि अधिग्रहण[89]	स्वास्थ्य समस्याओं की रिपोर्ट नहीं की गई। हालांकि विद्रोही समूहों द्वारा हिंसा में वृद्धि हुई है।[10]	परियोजना कार्यान्वयन में देरी[11]
रखाइन और अराकान क्षेत्र की जैव विविधता, पारिस्थितिकी पर प्रभाव[12]	आजीविका के नुकसान की सूचना दी[13] [14]	सीमा पार पारिस्थितिकी और जैव विविधता पर कोई प्रभाव नहीं रिपोर्ट किया गया

रवांडा-भारत न्याबोरोंगो पावर प्लांट

न्याबारोंगो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन रवांडा में स्थित 28 मेगावाट (38,000 एचपी) हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जिसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) और एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा भारत की क्रेडिट लाइन के हिस्से के रूप में कमीशन किया गया है। माना जाता है कि हाइड्रो पावर स्टेशन रवांडा की उत्पादन क्षमता को 114 मेगावाट से बढ़ाकर 147 मेगावाट[78] कर देगा और यह देश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन होगा।[79] इस परियोजना में एक बांध शामिल है, जो नदी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, मवोगो नदी पर, जो न्याबारोंगो नदी की सहायक नदियों में से एक है।

पावर स्टेशन रवांडा के दक्षिणी प्रांत में मुशीशिरो, मुहंगा जिले के पास, न्याबारोंगो नदी के पार स्थित है। यह स्थान रवांडा की राजधानी और सबसे बड़े शहर किगाली के दक्षिण-पश्चिम में सड़क मार्ग से लगभग 75 किलोमीटर (47 मील) की दूरी पर स्थित है।[80]

भारत द्वारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से दो फर्मों को 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्रेडिट देने की पेशकश के बाद यह परियोजना पूरी हुई, जबकि रवांडा ने शेष 17.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर[81] का योगदान दिया। इससे पहले 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दो एलओसी रवांडा सरकार को दिए गए थे।[82] रवांडा सरकार ने पावर स्टेशन को उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है और इस तरह के बड़े संरचना निर्माण के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और एलओसी प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की गई।[83] यह भी देखा गया है कि इस परियोजना से देश के लिए पेट्रोलियम आयात में मामूली कमी आई है और यह जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ा रही है।[13]

75 chin-human-rights-organisation-project-kaladan-movement-external-evaluation-report.pdf (norad.no)
76 Inside_Kaladan Movement Briefer_English [2].indd (burmariversnetwork.org)
77 The Trouble With India's Projects in Myanmar – The Diplomat
78 BHEL commissions hydro power plant in Rwanda, Africa - The Economic Times (indiatimes.com)
79 Exim Bank of India's LOCs: Boosting India's international trade (indiainfoline.com)
80 Distance between Kigali (Kigali) and Mushishiro (Gitarama) (Rwanda) (globefeed.com)
81 India and Rwanda Seal Nyabarongo II Power Deal – KT PRESS
82 Slide 1 (ris.org.in)
83 India, Rwanda become strategic partners | Business Standard News (business-standard.com)

मवोगो सहायक नदी

बांध मवोगो नदी पर बनाया गया है, जो न्याबोरोंगो नदी की एक सहायक नदी है, यह नील नदी बेसिन में न्याबारोंगो नदी-अपस्ट्रीम की रचना करने वाली 3 सहायक नदियों में से एक है। यह तीन मुख्य सहायक नदियों और ऊपरी न्याबारोंगो नदी के साथ दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाला एक लंबा जल क्षेत्र है, उनमें से मवोगो नदी जो जल क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी कोने से निकलती है और मबिरुरुमे के साथ इसके संगम पर न्याबारोंगो नदी में मिल जाती है।

मवोगो नदी के आस पास एक बसा हुआ समुदाय है जो बड़े पैमाने पर कृषि से जीवन बसर करता है।[84] खनिजों की सफाई के लिए न्यानजा धारा का उपयोग करते हुए खनन गतिविधि के परिणामस्वरूप मवोगो नदी आर्द्रभूमि भारी प्रदूषण में है।[85] [86]

न्याबोरोंगो पावर परियोजना का प्रभाव विश्लेषण

इस बात के सीमित प्रमाण है कि भारतीय एलओसी के सहयोग से बना न्याबोरोंगो परियोजना से किसी भी मानवाधिकार, वित्तीय संकट और पारिस्थितिक और पर्यावरणीय पतन में सहयोग किया है। हालाँकि, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ थीं कि मवोगो ऊपरी जल क्षेत्र पर भू-वैज्ञानिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा । यह प्रमुख रूप से वर्तमान खनन गतिविधियों के कारण है, जिन्होंने अवसादन में योगदान दिया है,[87] जिन्हें सीधे तौर पर भारत द्वारा विकसित पावर परियोजना के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

प्रभाव विश्लेषण

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव	मध्यम स्तर पर प्रभाव	विस्तृत स्तर पर प्रभाव
जबरन अधिग्रहण की कोई रिपोर्ट नहीं की गई	कोई स्वास्थ्य समस्या रिपोर्ट नहीं की गई	ईआईए रिपोर्ट सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है
मवोगो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र की जैव विविधता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं	रोजगार वृद्धि के कम प्रमाण और आजीविका के लिए खतरा	ऋण समस्या की कोई रिपोर्ट नहीं हुई

भारत-रवांडा विकास परियोजनाएं

ग्रामीण रवांडा में 35 स्कूलों का सौर विद्युतीकरण 2014 में रुपये के अनुदान के तहत पूरा किया गया था। भारत सरकार से 2.59 करोड़। - रवांडा भारत के विकासात्मक नियंत्रण रेखा के प्रमुख लाभार्थियों में से एक रहा है।

- भारत ने निर्यात लक्षित सिंचित कृषि परियोजना के विकास और इसके विस्तार के लिए 2013 में कुल 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एलओसी का विस्तार किया है।
- 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 81 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के एलओसी के लिए एक समझौता ज्ञापन और 24 मई 2017 को भारत के एक्ज़िम बैंक और रवांडा सरकार के बीच 4 व्यावसायिक ऊष्मायन केंद्रों पर हस्ताक्षर किए गए।
- बेस-बुटारो-किदेहो सड़क के उन्नयन के लिए यूएस $ 66.6 मिलियन के एलओसी पर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 14 मई 2018 को रवांडा के।
- अब तक रवांडा तक विस्तारित एलओसी की कुल मात्रा (जुलाई, 2018 में रवांडा की यात्रा के दौरान माननीय पीएम मोदी द्वारा घोषित दो एलओसी सहित) यूएसडी 547 मिलियन है।
- अब तक रवांडा तक विस्तारित एलओसी की कुल मात्रा (जुलाई, 2018 में रवांडा की यात्रा के दौरान माननीय पीएम मोदी द्वारा घोषित दो एलओसी सहित) यूएसडी 547 मिलियन है।

84 PD NYAMAGABE Revised version.pdf (fonerwa.org)
85 GLOWS_techpub_cover_sans_line (rwb.rw)
86 Nyabarongo upstream watershed rehabilitation plan (rwb.rw)
87 Ibid

नेपाल-भारत कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन

नेपाल सरकार (जीओएन) ने कोशी कॉरिडोर 220 kv ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के निर्माण के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ डॉलर क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस परियोजना के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) लाभार्थी है। भारतीय कांट्रेक्टर लार्सन एंड टर्बो 25.29 मिलियन डॉलर की लागत से कॉरिडोर परियोजना के दूसरे घटक के तहत बसंतपुर, बनेश्वर और तुमलिंगतार में तीन सबस्टेशन का निर्माण कर रहा है। बिजली प्राधिकरण ने जून 2016 में सबस्टेशन पर काम शुरू किया और फरवरी 2020 तक पूरा करने की समय सीमा तय की है।[88]

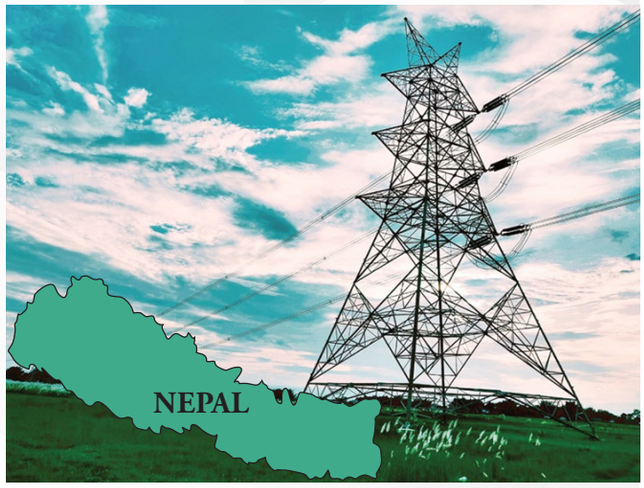

ट्रांसमिशन लाइन नेपाल के कोशी और मेची क्षेत्र में चयनित जल विद्युत परियोजनाओं को बिजली निकासी में मदद करेगी जिन्हें निकट भविष्य में संचालित किया जाना है। कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन भोजपुर, संखुवासभा, तेहराथुम और टेपेलेजुंग प्रांत में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न बिजली प्रदान करेगी। यह लाइन राष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेगी।[89] [90]

परियोजना विवरण

इस परियोजना में निम्नलिखित चार घटक शामिल है:

1) इनारुवा (सुनसारी जिला) से बसंतपुर (तेरहथुम जिला) से खंडबाड़ी (संखुवासभा जिला) तक 110 किलोमीटर लंबी डबल सर्किट 220 kv ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण;
2) खंडबाड़ी, बनेश्वर और बसंतपुर में 220/132/33/11 kv सबस्टेशन का निर्माण;
3) 30 किलोमीटर डबल सर्किट 220 kv ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण बसंतपुर (तेरहथुम जिले) से हैगपांग (तपलेजंग जिले) तक;
4) तापलेजंग जिले के हैगपांग में 220/132/33/11 kv सबस्टेशन का निर्माण।[91]

परियोजना से उत्पन्न चिंताएं

वनों की कटाई, पर्यावरणीय गिरावट, पर्यटन पर रोक आदि विभिन्न मामलों पर स्थानीय समुदायों द्वारा विरोध के कारण कोशी ट्रांसमिशन लाइन को देरी का सामना करना पड़ा।[92]

- स्थानीय वन अधिकारी परियोजना की प्रगति में बाधा डाल रहे है और परियोजना अधिकारियों को सबस्टेशनों के निर्माण के लिए स्थानीय नदियों से निर्माण सामग्री निकालने से रोक रहे है।[93] जैसा कि स्थानीय लोगों ने प्रमाणित किया है, यह परियोजना पर्यावरणीय क्षति का कारण भी बन सकती है।
- कोशी कॉरिडोर परियोजना के दूसरे पैकेज, जिसमें उपरोक्त सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है, को आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसका अनुबंध दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया गया है जो सार्वजनिक खरीद अधिनियम के खिलाफ है। अधिनियम में कहा गया है कि अनुबंध सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाना चाहिए।[94]
- इनारुवा से टापलेजंग तक ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर - कॉरिडोर के रास्ते में पड़े पेड़ों को काटने से संबंधित मुद्दों के कारण निर्माण कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना कॉरिडोर के लिए लगभग 9,000 पेड़ों को काटना होगा।[95] इसे हल करने के लिए धरान क्षेत्र में कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन

88 english_enc_-605thissue(18-24_may_2019).pdf (ippan.org.np)
89 NEA Resumes The Construction of 220 kV Kosi Corridor Transmission Line | New Spotlight Magazine (spotlightnepal.com)
90 Final-ESMF-for-PSRSHDP.pdf (nea.org.np)
91 Koshi Corridor 220 KV Transmission line: Total Management Services (tms.com.np)
92 Construction of Koshi Corridor faces delay - The Himalayan Times - Nepal's No.1 English Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News
93 Koshi corridor power line project faces new setback, likely to miss deadline by 10 months (kathmandupost.com)
94 Construction of Koshi Corridor faces delay – Bolchha Nepal
95 Construction of Koshi Corridor faces delay - The Himalayan Times - Nepal's No.1 English Daily Newspaper | Nepal News, Latest Politics, Business, World, Sports, Entertainment, Travel, Life Style News

परियोजना की समस्याओं को हल करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के अनुसार, सुनसारी के मुख्य जिला अधिकारी के समन्वय में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है।[96]

2019 तक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) द्वारा धरान उप-महानगरीय शहर के स्थानीय लोगों के साथ मतभेदों को हल करने के बाद कोशी कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन पर काम फिर से शुरू हो गया है। पावर यूटिलिटी के अधिकारियों के अनुसार, एनईए द्वारा अंतिम रूप दिए गए मार्ग पर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण पर स्थानीय इकाई को अब कोई आपत्ति नहीं है।[97]

प्रभाव विश्लेषण

सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव	मध्यम स्तर पर प्रभाव	विस्तृत स्तर पर प्रभाव
परियोजना के खिलाफ स्थानीय समुदाय, वन अधिकारियों का विरोध	कोई स्वास्थ्य समस्या रिपोर्ट नहीं की गई	बोलीदाताओं के चयन में गैर-पारदर्शिता के मुद्दों की सूचना दी गई
9000 पेड़ काटे गए	क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई	कोई ऋण समस्या रिपोर्ट नहीं की गई

सोलू ट्रांसमिशन कॉरिडोर लाइन का रुकना

कोशी पावर स्टेशन की प्रगति को रोकने की तर्ज पर, अब सोलू ट्रांसमिशन कॉरिडोर जिसे एक्जिम बैंक द्वारा 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्ट लोन के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है, समान चुनौतियों का सामना कर रहा है। उदयपुर जिले के कटारी नगर पालिका के मारुवा हरित सामुदायिक वन के उपभोक्ताओं द्वारा परियोजना कार्य में बाधा डाली गई, भूमि के मुआवजे की मांग, ट्रांसमिशन लाइन के मार्ग की मांग और ट्रांसमिशन लाइन टावर को कहीं और स्थानांतरित करने की मांग की।[98] हालांकि, अब मुद्दों को हल करने के साथ, ट्रांसमिशन कॉरिडोर जल्द ही फिर से शुरू होगा जो कोविड -19 के कारण अत्यधिक विलंबित हो गया था।[99]

ग्लोबल साउथ में भारत के सहयोग से अन्य संरचना परियोजनाएं

ऐसे अन्य कई देश है जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय वित्त पोषण से लाभान्वित हुए है, जिससे ग्लोबल साउथ देशों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ कुछ स्तर तक कम करने में मदद मिली है।[100] इनमें से कई परियोजनाएं भारतीय एलओसी का हिस्सा है और रियायती दरों[101] पर प्रदान की गई है और भारत और ग्लोबल साउथ के बीच विकास साझेदारी को गहरा करती है।

- *टोगो सौर ऊर्जा परियोजना का वित्तपोषण*: भारतीय एक्ज़िम बैंक सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा के माध्यम से 350 इलाकों के विद्युतीकरण के लिए टोगो सरकार को 40 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान कर रहा है। इस परियोजना से टोगो में बिजली की पहुंच में सुधार होगा। आवंटित राशि से 500 स्कूलों में ऑफ-ग्रिड सौर तंत्र की स्थापना के माध्यम से 350 इलाकों के विद्युतीकरण होगा। टोगो सरकार प्रभावित इलाकों में 12,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए नए फंड का इस्तेमाल करेगी। इस स्वच्छ ऊर्जा परियोजना से कृषि क्षेत्र को लाभ होगा, क्योंकि यह 2,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई तंत्र के अधिग्रहण में भी मदद करेगा। पीने के पानी के क्षेत्र में, टोगो सरकार ने 500 पेयजल आपूर्ति तंत्र (एईपी) को सौर-संचालित पंपिंग सिस्टम से लैस करने की योजना बनाई है।[102]
- *तंजानिया में जल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाना*: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने अफ्रीकी देश में जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए तंजानिया को 500 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 3,542 करोड़

96 Taskforce formed to solve problems facing Koshi corridor transmission line | NepalEnergyForum
97 Work resumes in Koshi Corridor - myRepublica - The New York Times Partner, Latest news of Nepal in English, Latest News Articles (nagariknetwork.com)
98 Solu Corridor transmission line project to resume work | NepalEnergyForum
99 Solu corridor transmission line project deadline extended for the fourth time (kathmandupost.com)
100 India's Lines of Credit to Africa in Health: Opportunity to Build a Key Pillar to the Economy | ORF (orfonline.org)
101 India-Africa relations: Partnership, COVID-19 setback and the way forward | ORF (orfonline.org)
102 TOGO: Exim Bank of India Finances the Electrification of 350 Localities Via Solar - World-Energy

रुपये) की ऋण सुविधा प्रदान की है। एक्ज़िम बैंक ने 10 मई, 2018 को तंजानिया सरकार के साथ जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तपोषण के उद्देश्य से 500 मिलियन अमरीकी डालर की भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।[103]

- *अफगानिस्तान में संरचना का विस्तार*: भारत अफगानिस्तान को उसकी विभिन्न संरचना विकास परियोजनाओं में मदद करता रहा है।[104] प्रयासों में जरंज-डेलाराम राजमार्ग का निर्माण, पुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण, सलमा बांध का निर्माण, 11 प्रांतों में दूरसंचार संरचना की पुनः स्थापना, अफगान संसद का निर्माण और पूरे देश में टेलीविजन नेटवर्क का विस्तार शामिल है।[105]
- *मंगोलिया की ऊर्जा जरूरतों का विकास*: मंगोल रिफाइनरी परियोजना भारत सरकार द्वारा अपने लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) कार्यक्रम के तहत शुरू की गई सबसे बड़ी परियोजना है और इससे मंगोलिया की ईंधन आयात निर्भरता में कुछ कमी आने की उम्मीद है। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी को भारत से 1.236 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का उपयोग करके 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृत लागत पर बनाया जाएगा।[106] भारत ने संरचना के विकास के लिए एलओसी भी प्रदान किया है और भूमि से घिरे मध्य एशियाई राष्ट्र के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है।[107]
- *जिम्बाब्वे में बिजली आपूर्ति का विकास*: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने जिम्बाब्वे गणराज्य के साथ दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को भारत सरकार द्वारा समर्थित ऋण सहायता (एलओसी) उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया और जिम्बाब्वे गणराज्य में पुनर्मूल्यांकन/बढ़ी हुई परियोजना लागत पर बुलावायो थर्मल पावर प्लांट के नवीनीकरण/विकास के वित्तपोषण के उद्देश्य से 23 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया।[108]
- *जलवायु परिवर्तन से कैरेबियाई देशों की रक्षा करना*: जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से लड़ने के लिए भारत ने जलवायु संरक्षण परियोजनाओं के लिए कैरिबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्किट (कैरिकॉम) के सदस्य देशों को ऋण सहायता के रूप में 150 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान दिया।[109] कैरिबियाई राष्ट्र ज्यादातर छोटे द्वीपों से बने है और जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित हुए है।[110]
- *मालदीव में कनेक्टिविटी के लिए संरचना क्षमता विकसित करना*: एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया (एक्ज़िम बैंक) ने 12 अक्टूबर, 2020 को मालदीव गणराज्य में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी - (मेल' से थिलाफुशी लिंक) परियोजना शुरू करने के उद्देश्य से मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ 400 अमरीकी डालर की ऋण सहायता (एलओसी) उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता किया है।[111] ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) मालदीव में सबसे बड़ी सामाजिक संरचना परियोजना होगी, जो माले को तीन पड़ोसी द्वीपों- विलिंगिली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी से जोड़ती है।[112] इसके अलावा, भारत पड़ोसी द्वीप राष्ट्र में खेल संरचना निर्माण में भी निवेश कर रहा है।[113]
- *श्रीलंका में सौर ऊर्जा का वित्तपोषण*: भारत ने विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) प्रदान की। यह वित्तीय मदद 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा देश की 70 प्रतिशत बिजली आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित करके श्रीलंका सरकार को अपने सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।[114] भारत ने कई अवसरों पर विभिन्न संरचना विकास परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को एलओसी अनुदान प्रदान किया है।[115]

103 Exim Bank extends USD 500 mn loan to Tanzania for water projects | Business Standard News (business-standard.com)
104 In his remarks at the Shanghai Cooperation Organization, Defence Minister Rajnath Singh highlighted that India was involved in 500 development projects in Afghanistan. Rajnath Singh highlights Afghan crisis at SCO, talks about 500 development projects by India | India News (timesnownews.com)
105 India's Development Aid to Afghanistan: Does Afghanistan Need What India Gives? – The Diplomat
106 India helps Mongolia for its first petrochemical refinery (livemint.com)
107 PM Narendra Modi announces $1 billion line of credit for Mongolia | India News - Times of India (indiatimes.com)
108 Reserve Bank of India - Notifications (rbi.org.in)
109 India extends $150 million line of credit to CARICOM nations for climate conservation projects | Business Standard News (business-standard.com)
110 A Caribbean strategy to cope with climate change | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (unesco.org)
111 Reserve Bank of India - Notifications (rbi.org.in)
112 India to provide $500 million assistance for connectivity project in Maldives - Projects & Tenders - Construction Week Online India
113 India pledges USD 40 million for development of Maldives' sports infrastructure | SunOnline International
114 India Extends $100 Million Line Of Credit To Sri Lanka For Solar Energy Projects (solarquarter.com)
115 India announces $400 million line of credit for infrastructure in Sri Lanka - The Hindu BusinessLine

सुझाव और निष्कर्ष

भारत को संरचना से संबंधित अपनी विकास सहयोग नीतियों में एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़ों के साथ, यह माना जा सकता है कि कई परियोजनाएं कुछ घरेलू चुनौतियों का सामना कर रही है जिन्हें सकारात्मक कार्यों, स्थानीय समुदायों और हितधारकों के साथ आम सहमति बनाने के माध्यम से पूर्ण करने की आवश्यकता है। भारत की बहुत सी ऋण व्यवस्थाएं अधिकारों, पर्यावरण और भौगोलिक क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है और इस प्रकार ग्लोबल साउथ में विकास परियोजनाओं का सहयोग करने के लिए सरकार के नेक इरादे को साबित किया है। हालांकि, संरचना में भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत है और इसमें विदेश मंत्रालय के तहत नियामक निरीक्षण शामिल होना चाहिए। आंकड़ों की कमी इस बात की पुष्टि करती है कि संरचना परियोजनाओं से मिली सकारात्मकता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। सहायक साहित्य और वास्तविक प्रमाण कई उदाहरणों की ओर इशारा करते है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र, जी 7, जी 20 और ब्रिक्स द्वारा बताये गए संरचना विकास के अनुरूप संरचना परियोजनाओं की पूर्ण लागत बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए अंतरराष्ट्रीय संकेतकों का उपयोग करने और एलओसी, बाइलेटरल जीआईए प्रोजेक्ट्स के लिए मास्टर संकेतक विकसित करने के साथ-साथ संभावित समावेशी उपाय किए जा सकते है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और विभिन्न सामाजिक ढांचे को एमओयू और परियोजना प्रस्तावों में अंतर्निहित करने की आवश्यकता है और उन्हें सार्वजनिक करने की भी आवश्यकता है। यह देखा गया कि कई ईआईए जांच और संदर्भ के लिए मूल्यांकन उपलब्ध नहीं थे जिससे परियोजना और उसके प्रबंधकों द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता का पता लगाना मुश्किल हो गया। स्पष्ट रूप से, इन परियोजनाओं का विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है और लाभार्थी देशों द्वारा विकसित परियोजना प्रस्ताव में इसे संकेतक के रूप में शामिल करने का एक तरीका हो सकता है। पारदर्शिता का भी अभाव है, और एक उदाहरण उपलब्ध था जहां परियोजना का संचालन किया गया था। कम बोली प्रक्रियाओं पर भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी जिसमें एक भारतीय फर्म शामिल थी। इससे दुनिया भर में अपनाई जाने वाली एक पारदर्शी, डिजिटल प्रणाली का उपयोग करके प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है जो परियोजना के डिजाइन, निर्माण से लेकर संचालन और प्रबंधन तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देगा। इसी तरह, यह महसूस किया गया था कि कुछ निहित समूह जानबूझकर कार्य ठप करने के उपाय कर रहे थे जिससे द्विपक्षीय संबंधों में बाधा उत्पन्न हुई। इन्हें मजबूत राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है क्योंकि यह आक्रोश जनता की राय पर हावी है और भारत की सुरक्षा, वाणिज्यि और आर्थिक हितों को भारी नुकसान पहुंचाते है। इसी तरह, मुआवजे के उपायों को विकास सहयोग समझौतों के माध्यम से बनाया जाना चाहिए जो परियोजनाओं के खिलाफ स्थानीय आक्रोश को कम करेंगे । हालांकि शोध से आजीविका की हानि की पुष्टि नहीं हुई है, सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से सकारात्मक लाभ बताते हुए भारत के एलओसी, द्विपक्षीय निवेश आदि के माध्यम से संरचना परियोजनाओं के लिए संभावित प्रयास किए जा सकते है। इस रिपोर्ट से सकारात्मक विकास देखा गया है - भारत स्वच्छ ऊर्जा संरचना विकास में निवेश कर रहा है। लेकिन यह स्थानीय जैव विविधता और क्षेत्र की पारिस्थितिक को प्रभावित करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर एलायंस (आईएसए) और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के तहत सहयोग को मजबूत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। अंत में, परियोजनाओं की सकारात्मक आलोचना करने के लिए दोनों देशों की सिविल सोसाइटी के लिए स्थान होना चाहिए। नीति निर्माण में सिविल सोसाइटी संगठनों की अनुपस्थिति द्विपक्षीय प्रयासों का प्रतिकार कर सकती है। वैश्विक शासन मंचों में संरचना नीतियों के विकास में पहले से ही सिविल सोसाइटी एक सक्रिय हितधारक है, द्विपक्षीय संलग्नता में भागीदारी भारत के विकास सहयोग कार्यक्रम में सहायक होगी। इन सबसे ऊपर, यह स्पष्ट है कि भारत के विकास सहयोग को भू-राजनीतिक क्षेत्र में अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए ग्लोबल साउथ देशों को सक्रिय रूप से स्थायी संरचना का सहयोग करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

अलाघ, योगिन्दरे के. "टेक्नोलॉजी, रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इन दी इंडियन सबकॉन्टीनेंट" वर्ल्ड अफेयर्स: दी जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल इश्यूज 3 (1991): 57-62. 30 जुलाई, 2021 को एक्सेस किया गया।

अशरफ एफ (2008) इंडिया-म्यांमार रिलेशन्स, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, 28(1), 223-233

एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टिट्यूट (2015) क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने में (पीपी। 53-112), ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस।

आजाद ए.एस डब्ल्यू नसरीन, और जे सुल्ताना (2006) बांग्लादेश में ऊर्जा की खपत और CO□ उत्सर्जन की स्थिति, अंबियो 35(2), 86-88

बाबुगुरा, अग्नेस - जेंडर एक्वालिटी: ए कॉर्नरस्टोन फॉर ए ग्रीन इकॉनमी। साउथ अफ्रीकन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स, 2017

बेलफिगलिओ, वी (1972) भूटान के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंध। एशियन सर्वे, 12(8), 676-685

भोंसले, एम (2015) एवोल्यूशन ऑफ़ दी अराकन 'प्रॉब्लम' इन बर्मा, प्रोसीडिंग्स ऑफ़ दी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, 76, 631-636

ब्लैंक, पी. (1984) एक विकासशील देश में पर्यावरण स्वास्थ्य और विकास: रवांडा, एक केस स्टडी। जर्नल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, 5(2), 271-288

बोस एस (2007) (प्रतिनिधि) इंस्टिट्यूट ऑफ़ पीस एंड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज

ब्रॉच, एम (2017) सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुबंध: संरचना निवेश परियोजनाओं के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सह-लाभ सुनिश्चित करना (पीपी 5-14, प्रतिनिधि)। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी)

चतुर्वेदी, एस. (2018) बहुपक्षवाद और विकसित वैश्विक व्यवस्था के लिए भारत का दृष्टिकोण। इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल, 13(2), 128-135

क्ले डी, रीडेन टी, एंड कंगास्निमी जे (1998) हाईलैंड ट्रॉपिक्स में सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन: रवांडा फार्मर्स इनवेस्टमेंट्स इन लैंड कंजर्वेशन एंड सॉयल फर्टिलिटी। इकनोमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, 46(2), 351-377

कॉर्डेल, के एंड ली, सी (2021) (प्रतिनिधि) सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस)

कोटुला, एल (2015) (प्रतिनिधि) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एन्वायरोमेंट एंड डेवलपमेंट

कोटुला, एल (2015) लैंड राइट्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रीटीस : एक्सप्लोरिंग दी इंटरफ़ेस (पीपी 15-24, रिप्रेजेन्टेटिव) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एन्वायरोमेंट एंड डेवलपमेंट

कॉक्स, पी (2020) थिओराइसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर: ए पॉलिटिक्स ऑफ स्पेस एंड एजेस। इन कॉक्स पी एंड कोग्लिन टी (एड्स), दी पॉलिटिक्स ऑफ़ साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: स्पेस और (इन) इक्वालिटी (पीपी 15-34), ब्रिस्टल: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस

डेवेल्टेरे पी, हयसे एच, एंड वैन ओन्गेवेल जे (2021) दी फोर्थ पिलर : टुवार्ड्स ए होल ऑफ़ सोसाइटी एप्रोच, इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन टुडे: ए रेडिकल शिफ्ट टुवार्ड्स ए ग्लोबल पेरडिगम, (पीपी 187-232), ल्यूवेन (बेल्जियम): ल्यूवेन यूनिवर्सिटी प्रेस

एस्केलेरस एम, और रजिस्टर सी (2016) प्राकृतिक आपदाओं के समय कम गुणवत्ता वाली उच्च लागत की संरचना। दी जर्नल ऑफ़ डेवलपिंग एरियाज 50(1), 103-122

गोर, सी (2017) अफ्रीका में बिजली, संरचना और बांध। अफ्रीका में बिजली: युगांडा में परिवर्तन की राजनीति (पीपी 12-26) वुडब्रिज, सफ़ोक (जीबी) रोचेस्टर, न्यूयॉर्क यूएसए: बॉयडेल और ब्रेवर

गुनातिलेक, एच एंड रोलैंड-होल्स्ट, डी (2016) बांग्लादेश के लिए स्मार्ट ऊर्जा विकल्प (पीपी 2-9, प्रतिनिधि) कोपेनहेगन कन्सेंसस सेंटर

गुप्ता, ए (2009) द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू-नेपाल: चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। इंडियन जर्नल ऑफ एशियन अफेयर्स, 22(1/2), 57-73

हारन, वी (2018) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग। इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल, 13(3), 195-208

हार्टले बी एंड वैन मीटर एच (2011) पानी का मानव अधिकार: मानव अधिकार आधारित प्राथमिकता दृष्टिकोण के लिए प्रस्ताव। विलमेट जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्प्यूट रेसोलुशन, 19(1), 66-102

आईसीएचओआरडी, रॉबर्ट एफ। विकासशील देशों में ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव : बांग्लादेश में भू-राजनीति, गरीबी और जलवायु परिवर्तन, अटलांटिक परिषद, 2020

जॉनसन ओ, मुहोजा सी, ओगेया एम, ओगोल टी, बिनिंगटन टी, फ्लोर्स एफ, और कार्लबर्ग एल (2018) (प्रतिनिधि) स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान

जोसेफ सी एम (2007) भारत-भूटान संबंध: एक अवलोकन। इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल, 2(1), 88-101

कांग एच (2010) (प्रतिनिधि) इंस्टिट्यूट ऑफ़ पीस एंड कनफ्लिक्ट स्टडीज

कंवल, जी (2010) ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया-म्यांमार रिलेशन्। इन रिफेल एल (एड.), म्यांमार/बर्मा: इनसाइड चैलेंजेज, आउटसाइड इंटरेस्ट्स (पीपी. 134-149) ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन प्रेस

कोप्पुझा, ए (2008) (प्रतिनिधि) इंस्टिट्यूट ऑफ़ पीस एंड कनफ्लिक्ट स्टडीज

लीब, एल (2011) रेकॉन्फ़िगरेशन ऑफ़ दी ह्यूमन राइट्स सिस्टम इन लाइट ऑफ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड दी टू लेवल कन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ़ एन्वाइरोमेन्टल राइट्स। इन ह्यूमन राइट्स एंड दी एन्वाइरोमेन्ट: फिलोसोफिकल, थ्योरेटिकल एंड लीगल पर्सपेक्टिव्स (पीपी 109-156) लीडेन; बोस्टन: ब्रिल

लुफम्पा सी, मुबिला एम, और येप्स टी (2017) संरचना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण। लुफुंपा सी एंड एनक्यूब एम (एड्) में, अफ्रीका में संरचना: भविष्य में विकास के लिए सीख (पीपी 423-520) ब्रिस्टल, यूके; शिकागो, आईएल, यूएसए: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस

मैरी कायितेसी-ब्लेविट (2006) फंडिंग डेवलपमेंट इन रवांडा: द सर्वाइवर्स पर्सपेक्टिव। डेवलपमेंट इन प्रैक्टिस, 16(3/4), 316-321

मैसे, जी (2016) समुदाय के स्तंभ: तंजानिया में स्वयंसेवको को भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे प्रशिक्षित करे (पीपी 2-5, प्रतिनिधि) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एन्वाइरोमेंट एंड डेवलपमेंट

मॉर्फेट, जे (2016) पर्यावरण और हरित संरचना। संरचना वितरण योजना : एक प्रभावी अभ्यास दृष्टिकोण (पीपी 55-72)। ब्रिस्टल, यूके; शिकागो, आईएल, यूएसए: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस

न्यूमैन, एम (2014) दी लॉन्ग एमेर्जेंस ऑफ़ दी इंफ्रास्ट्रक्चर इमरजेंसी, टाउन प्लानिंग रिव्यू, 85(6), 795-806

नीलसेन, के (2011) भूमि, कानून और विरोध। इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, 46(41), 38-40

ओ मानिक, जे (1992) मानव अधिकार और विकास । मानवाधिकार त्रैमासिक, 14(1), 78-103. डीओआई :10.2307/762553

पट्टनायक, एस (2010) (प्रतिनिधि) इंस्टिट्यूट ऑफ़ पीस एंड कॉनफ्लिक्ट स्टडीज

प्रधान, एस (2008) कोऑपरेशन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सीईएसएसडी): ए साउथ-साउथ पर्सपेक्टिव, इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल, 3(3), 68-91

क्वान, एच (2005) स्वदेशी लोगों के अधिकार और विकास प्रक्रिया। मानवाधिकार तिमाही, 27(2), 652-682

रूंडे डी (2017) (प्रतिनिधि) सेण्टर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस)

सानो, एच (2000) विकास और मानवाधिकार: मानव अधिकारों और विकास का आवश्यक, लेकिन आंशिक एकीकरण। मानवाधिकार तिमाही, 22(3) 734-752

सरकार, टी (2012) भारत-भूटान संबंध। द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 73(2) 347-352

शर्मा, एच. (1994) भूटान और इसके क्षेत्रीय सुरक्षा पर्यावरण। इंडिया क्वार्टरली, 50(3), 25-42

शर्मा आर और अधिकारी ए (1991) नेपाल में ऊर्जा और पर्यावरण। ऊर्जा और पर्यावरण, 2(4) 358-367

सिंह, आर (2010) नेपाल की भू-राजनीतिक स्थिति और भारतीय सुरक्षा पर इसका प्रभाव। द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 71(4), 1281-1292

सिंह आर, और सिंह वी (1999) भारत और नेपाल के बीच आर्थिक बातचीत। प्रोसीडिंग्स ऑफ़ दी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस , 60, 995-1000

स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी (2016) बियॉन्ड इकोनॉमिक्स: गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। वाल्टर आई. (एड), द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस चैलेंज (पीपी 39-46) कैम्ब्रिज, यूके: ओपन बुक

टेस्टोनी ए (2018) अफ्रीका में भारतीय विकास सहयोग नीतियों का विकास: एक विशिष्ट और सक्रिय भूमिका का पीछा करते हुए, रिविस्टा दी स्टडी पॉलिटिक्स इंटरनेशनल, 85(4), 557-574

त्रिवेदी, एस (2017) वीविंग द मिसिंग लिंक्स इन इंडिया-म्यांमार रिलेशंस, वर्ल्ड अफेयर्स: द जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज, 21(4), 148-163

वालकॉट, एस (2009) भूटान में शहरीकरण, भौगोलिक समीक्षा, 99(1), 81-93

ज्यूरिक, डी (2006) भूटान में सकल राष्ट्रीय खुशी और पर्यावरण की स्थिति। भौगोलिक समीक्षा, 96(4), 657-681

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
INDIA

VANI
Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

www.vaniindia.org

About VANI

As a platform, it promotes voluntarism and creates space for voluntary action. As a network, it attempts to bring about a convergence of common sectoral issues and concerns for building a truly National agenda of voluntary action in the country. It also facilitates linkages of various efforts and initiatives of the voluntary sector.